● वर्ष-3
● अंक-04
रायपुर, शनिवार
12 अगस्त 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र का समापन हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र की कार्यवाही 20 जुलाई को शुरू हुई थी। हालांकि, मणिपुर मुद्दे को लेकर दोनों ही सदनों में पूरे सत्र के दौरान गतिरोध देखने को मिला। दोनों सदनों में सरकार की परीक्षा भी हुई। जहां लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त तरीके से बहस देखने को मिली तो वहीं राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पर सरकार की ताकत भी लोगों के सामने आई। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। मानसून सत्र में दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है, यह हम आपको बताते हैं।

लोकसभा की बैठक शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर मुद्दे सहित कुछ अन्य विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मानसून सत्र के दौरान कामकाज बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा से पहले बताया कि सत्र के दौरान 17 बैठक हुईं जिनमें 44 घंटे 13 मिनट कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता करीब 46 प्रतिशत रही। बिरला ने कहा

कि सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और इस पर 19 घंटे 59 मिनट चर्चा हुई तथा 60 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर सदन में गतिरोध कायम रहने के कारण कामकाज बाधित होने पर अफसोस जताया। राज्यसभा में मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और इस दौरान सदन की कुल 17 बैठकें हुईं। राज्यसभा ने सेवानिवृत्त हो रहे अपने नौ सदस्यों को शुक्रवार को विदाई दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। हालांकि इनमें से चार सदस्य पुनर्निर्वाचित हुए हैं। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जुगल सिंह लोखंडवाला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिनेश चंद्र अनावाडीया, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन, शांता छेत्री, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य शामिल हैं। इनमें से एस जयशंकर, डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन और सुखेंदु रॉय उच्च सदन के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य राघव चड्ढा को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण आचरण के चलते विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही, अशोभनीय आचरण तथा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किए गए आप सदस्य संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक बढ़ा दी गई। संसद ने 'केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023' और 'एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023' को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

सत्र के दौरान 22 विधेयक पारित किये गए

- सत्र के दौरान पारित किये गए महत्वपूर्ण विधेयकों में
- बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023,
- डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023,
- राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023,
- राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023,
- जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023,
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023
- अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023

निरस्त किया जाएगा राजद्रोह कानून

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त में पांच प्रण दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उससे मुक्ति पाना सबसे पहले काम है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी होने का ठप्पा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंश एक्ट पर था। 1830, 1856, 1872 उस दौरान इन सब चीजों को लाया गया और हम अब तक ढो रहे थे। आईपीसी का असल में नाम आयरिश पीनल कोड था। भारत के गृह मंत्री ने गुलामी की जंजीरों से पूरे सिस्टम को आजादी दी है। गृह मंत्री ने घोषणा की कि राजद्रोह कानून निरस्त कर दिया गया है। प्रस्तावित कानून में देशद्रोह शब्द नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए इसे धारा 150 से बदल दिया गया है। धारा 150 में कहा गया है- जो कोई, जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना; या ऐसे किसी भी कार्य

इन दिनों

✍ अमित शर्मा

आदिवासी मतदाताओं पर लगेगा चुनावी दांव

चुनावी राज्यों में भाजपा-कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे को मात देने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ की खबर दोनों दलों के लिए कुछ चिंता पैदा करने वाली है। आदिवासी समुदाय के नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सभी आदिवासी सीटों और कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सर्व आदिवासी समाज मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इन सभी चुनावी राज्यों के चुनाव में एक नया समीकरण पैदा हो जाएगा जो भाजपा-कांग्रेस दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाताओं का रुझान भाजपा-कांग्रेस में बंटा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन पर काफी हद तक कब्जा कर लिया था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भाजपा का जादू चला था तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का लगभग सफाया कर दिया था। उसने सबसे ज्यादा आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी कांग्रेस का आदिवासी सीटों पर दावा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन उसके बागी नेता अरविंद नेताम ने पार्टी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। यदि सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी समुदाय के मतदाताओं के एक हिस्से को आकर्षित किया तो भाजपा-कांग्रेस के समीकरण बदल सकते राजस्थान में कांग्रेस आदिवासी बहुल सीटों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाओं की शुरूआत कर उन्हें कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का काम किया है। उन्होंने आदिवासियों को देश का असली मूल निवासी बताकर उनकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। वहीं, भाजपा भी गुजरात से सटे आदिवासी इलाकों में बड़े नेताओं की मौजूदगी कराकर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। राज्य के निर्माण के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की दावेदारी कर रही भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। आदिवासी दिवस पर बीआरएस नेता के. कविता ने कहा है कि उनकी सरकार आदिवासी हितों के लिए पूरी तरह तैयार है। समान नागरिक संहिता से आदिवासी समुदाय के पारंपरिक रीति-रिवाजों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी समुदाय के लोगों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी। समान नागरिक संहिता से आदिवासी समाज को प्रभावित न होने देने का दावा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लिए 29 सीटें और राजस्थान में 25 सीटें आरक्षित हैं। तेलंगाना की 119 सीटों में से 12 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं।

बांके बिहारी की जमीन कब्रिस्तान के नाम कैसे हो गई: कोर्ट

मथुरा। मथुरा-वृंदावन मामले में भी सुगबुगाहट तेज हो चली है। एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और मथुरा की स्थानीय कोर्ट में जो कुछ हुआ वह काफी सकारात्मक रहा। इसके अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास से जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है उसके लिए भी योगी सरकार की जमकर सराहना हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की छाता तहसील के तहसीलदार को यह बताने का निर्देश दिया है कि बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज जमीन कैसे 2004 में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गई। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट

द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। हम आपको बता दें कि यह रिट याचिका, छाता के राजस्व अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की गई है। आवेदन में राजस्व प्रविष्टि सही करने की प्रार्थना की गई है जिसमें जमीन बांके बिहारी जी महाराज की जगह अवैध रूप से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहा कि कब्रिस्तान का नाम दर्ज करने के लिए भी एक आवेदन लंबित है क्योंकि प्रविष्टियां अब कब्रिस्तान से पुरानी आबादी में बदल दी गई हैं।

हम आपको याद दिला दें कि अदालत ने पिछले बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छाता तहसील के शाहपुर गांव में भूखंड संख्या 1081 पर उपलब्ध प्रविष्टियां बदलने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी कार्यवाही की गई है, उसका उल्लेख करने का निर्देश दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि भूखंड संख्या 1081 मूल रूप से बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज था जोकि 1375-1377एफ के अधिकारों के रिकॉर्ड से स्पष्ट है। बाद में वर्ष 2004 में इसे बदलकर कब्रिस्तान के नाम कर दिया गया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त, 2023 निर्धारित की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास साहित्य एवँ संस्कृति अकादमी के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवँ कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई ।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस ने बोये मणिपुर में नफरत के बीज: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा की वजह से पूरा का पूरा संसद सत्र बाधित रहा। संसद का सत्र समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधा तो वहीं भाजपा की ओर से भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर

निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में नफरत के बीज किसने बोये? इसका बीजारोपण कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान पूर्वोत्तर बम, बंद और विस्फोट के लिए जाना जाता था। आपकी नीति लुक ईस्ट थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति शुरू की। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। वहीं, युवा नेता ने आगे कहा कि केवल टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थक ही भारत माता को तोड़ने, मारने की सोच सकते हैं। उन्हें मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं है। वे संविधान, भारत माता की हत्या की बात करते हैं। राहुल गांधी को राजस्थान की महिलाओं की चिंता नहीं है, आप पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर की महिलाओं में अंतर करते हैं।

राहुल का नुस्खा गलत, मणिपुर का हल गोलियों से नहीं: सरमा

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर शांति के लिए राहुल गांधी का नुस्खा गलत है क्योंकि गांधी संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में सेना के हस्तक्षेप का सुझाव दे रहे हैं। हिमंत ने कहा, मणिपुर की स्थिति

का समाधान गोलियों से नहीं दिलों से निकलना चाहिए। अपने बयान में हिमंता ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने आइजोल में भी यही किया। बमबारी के बाद हिंसा कम हो रही थी। आज राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना को मणिपुर में हिंसा रोकनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इसका मतलब क्या है? क्या उन्हें नागरिकों पर गोलियां चलानी चाहिए? राहुल गांधी पर पलटवार करत हुए हिमंत ने कहा, क्या यह उनका नुस्खा है? वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? सेना कुछ भी हल नहीं कर पाएगी। वे केवल कुछ समय के लिए शांत हो पाएंगे और अस्थायी शांति ला पाएंगे। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बोलना चाहिए और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे बाहर चले गए। इससे उनका मंसूबा पूरी तरह उजागर हो गया कि विपक्ष की मंशा का मणिपुर से कोई लेना-देना नहीं है।

हाईकोर्ट के 23 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से 23 न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है, जिनमें गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत एम. प्रच्छक भी शामिल हैं, जिन्होंने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी से संबंधित 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सदस्यता वाले कॉलेजियम ने तीन अगस्त को हुई अपनी बैठक में 'बेहतर न्यायिक प्रशासन' के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के नौ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कॉलेजियम प्रस्ताव के अनुसार, इन नौ नामों में से चार-चार न्यायाधीश गुजरात तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों से, जबकि एक अन्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति प्रच्छक का तबादला गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय करने की सिफारिश की है।

कांग्रेस के डरो मत कैंपेन पर भाजपा का पलटवार

नई दिल्ली। जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी, तब कांग्रेस की ओर से एक अभियान चलाया गया था। उस नाम दिया गया था डरो मत। वहीं, अब भाजपा उसी कैंपेन को लेकर पलटवार कर रही है। भाजपा कह रही है, डरो मत

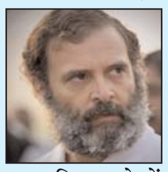

भागे। डरो मत को भाजपा ने बीच से लाल रंग से काटा भी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कांग्रेस ने कहा था कि आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के सूरत जिले की एक अदालत द्वारा पार्टी सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाना न्यायपालिका को प्रभावित करने का एक प्रयास है और लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, डरो मत। वहीं भाजपा ने अब इसे बढ़ाने की कोशिश की है। भाजपा यह बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी डरपोक हो गए हैं। तभी तो भाजपा की ओर से भी एक पोस्ट साझा किया गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी संसद से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई मौजूद हैं। पूरा का पूरा मामला तब का है।

मारे गए खालिस्तानी ने नहीं लिया था भारत का नाम

ओटावा। अलगाववादी तत्वों ने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन निज्जर के एक विश्वासपात्र ने कहा है कि कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उनके जीवन के संभावित खतरे के बारे में

जानकारी देते समय भारत का उल्लेख नहीं किया। खालिस्तान के समर्थक निज्जर को निशाना बनाए जाने से बचने के लिए स्थानांतरित होने और अपनी दिनचर्या बदलने की सलाह दी गई थी। निज्जर की हत्या के बाद से खालिस्तान समर्थक समूह कनाडा में भारत के राजनयिकों को निशाना बनाते हुए पोस्टर अभियान चला रहे हैं। जबकि अलगाववादी तत्वों ने ब्रिटिश कोलंबिया में कनाडा के सरे शहर में 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए नई दिल्ली को दोषी ठहराया है, खालिस्तानी व्यक्ति के एक करीबी विश्वासपात्र ने कहा है कि कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संभावित खतरे के बारे में जानकारी देते समय भारत का उल्लेख नहीं किया था। खालिस्तान के समर्थक निज्जर, जो निज्जर के बहुत करीबी थे, के साथ एजेंसियों की बातचीत के दौरान भारत को खतरे के स्रोत के रूप में नामित नहीं किया गया था।

खुद के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के समय गायब विपक्ष

अजय सेतिया

लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था। जैसे अब लोकसभा में मोदी सरकार को भारी बहुमत है, वैसे ही तब जवाहर लाल नेहरू को लोकसभा में अपार समर्थन था। लेकिन तब लोकसभा के 494 सदस्य हुआ करते थे, जबकि अब 545 सांसद हैं, तब से 51 सांसद ज्यादा हैं। उस अविश्वास मत में नेहरू सरकार के पक्ष में 347 वोट पड़े थे। 1963 को मिलाकर अब तक 27 बार विभिन्न सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। लेकिन अब तक का रिकार्ड 1963 का ही था, जब नेहरू को 494 के सदन में 347 सांसदों का समर्थन मिला। हालांकि वह नेहरू की एक दृष्टि से हार थी, क्योंकि सदन में कांग्रेस के अपने 361 सांसद थे, कांग्रेस के अपने ही 14 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में नेहरू सरकार के समर्थन में नहीं दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तब तक विभाजन नहीं हुआ था और लोकसभा में 29 सीटों के साथ वह प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, वह उस समय जनसंघ हुआ करती थी, और उस समय जनसंघ के 14 लोकसभा सदस्य थे।

नरेंद्र मोदी सरकार को नौ साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर मोदी को सदन में लाना चाहता था, जिसके लिए सरकार तैयार भी थी। जिद्द सिर्फ यह थी कि मणिपुर पर मोदी सदन में बयान दें, और बहस हो तो जवाब मोदी दें। बहस में हिसा लेते हुए अमित शाह ने याद दिलाया कि जब नरसिंह राव के शासनकाल में मणिपुर में सात सौ हत्याएं हुई थीं, तो लोकसभा में हुई बहस का जवाब गृह राज्यमंत्री राजेश पायलट ने दिया था। विपक्ष अपनी जिद्द के चलते अविश्वास प्रस्ताव ले आया, तो बहस में हिस्सा लेते हुए केबिनेट मंत्री किरन रिजीजू ने कहा था कि विपक्ष को बाद में पछतावा होगा कि वह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाई। वही हुआ, सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव का अपनी नौ साल की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए जम कर इस्तेमाल किया। असम के भाजपाई सांसद राजदीप राय बोल रहे थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में प्रवेश किया। उस समय सदन में लगाए गए नारों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नारों की भूमिका तय कर दी है। मोदी के सदन में प्रवेश करते ही जहां भाजपा

सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, वहीं विपक्ष की तरफ से इंडिया इंडिया के नारे लगाए गए। मोदी जब भाषण दे रहे थे, और सत्ता पक्ष से मोदी मोदी के नारे लगने लगे, तब भी विपक्ष ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। मोदी ने जो भाजपा की बैठक में कहा था, उसे सदन में भी दोहराया कि यह इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। मोदी ने अपने भाषण के आखिर में इंडिया गठबंधन को आतंकवाद और बर्बादी की गारंटी बताकर नारे लगवाए और देश को वादा किया कि वह भारत को विकसित देश बनाने की गारंटी देते हैं। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी के बाद विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करनी थी तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए। मोदी ने यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि मणिपुर की स्थिति हाईकोर्ट के फैसले के कारण पैदा हुई। कांग्रेस राज के समय मणिपुर में हुए दंगों और नरसंहारों का उल्लेख करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने में भी मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

अविश्वास प्रस्ताव के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था, इसलिए बहस में हिस्सा लेते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह नहीं होता कि सरकार हट जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। उन्होंने 1963 के जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया, जब जवाहर लाल नेहरू सरकार को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत था। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी कि विपक्ष को प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मानसून सत्र में सदन में नही आए थे, वह सत्र के आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए आए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए उलटे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने इंदिरा गांधी की ओर से कच्छदीव द्वीप श्रीलंका को उपहार में देने, मिजोरम में हवाई सेना से हमला करवाने और अकाल तख्त पर सेना से हमला करवाने के पुराने जख्म भी उधेड़े। उन्होंने पूर्वोतर के लोगों को 1962 में उनके भाग्य पर छोड़ देने वाले नेहरू के रेडियो प्रसारण का भी जिक्र किया। मोदी ने अपने भाषण के आखिर में पूर्वोत्तर की स्थिति पर विस्तार से बोला और आरोप लगाया कि पूर्वोतर की सभी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है। मोदी ने अपने जवाब में याद दिलाया कि विपक्ष जब उनके खिलाफ 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उन्होंने तब भी कहा था कि वह विपक्ष का खुद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है। वही हुआ, जनता 2019 में भाजपा और एनडीए को ज्यादा बहुमत से वापस लाई थी, और अब भी ज्यादा बहुमत से वापस लाएगी।

फर्जी राशन रोकने ई.केवाईसी सत्यापन अनिवार्य 55% हितग्राहियों का नहीं हो सका सत्यापन

कोरबा। फर्जी राशन वितरण को रोकने के लिए सभी हितग्राहियों का ई.केवायसी के अंतर्गत फिंगर प्रिंट मिलान करना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। एक जून से 31 जुलाई तक तीन बार तिथि बढ़ाया जा चुका है। इसके बाद भी जिले के 3.26 लाख राशनकार्ड हितग्राहियों में 55 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन हीं कराने वालों में ज्यादातर नाम्नी के सहारे राशन लेने वाले बुजुर्ग व दिव्यांग हैं। ऐसे हितग्राहियों का दुकान तक पहुंचना मुश्किल है। सत्यापन के अभाव में फर्जी राशन वितरण को रोकने में खाद्य विभाग नाकाम है।

सस्ता राशन वितरण प्रणाली आम हितग्राहियों के लिए जितना सुगम ही उतना ही इसे दुकान संचालकों ने उपरी कमाई का जरिया बना लिया है। राशन कार्ड का पिछले चार वर्षों से सत्यापन नहीं हुआ है। ऐसे में मृत हो चुके हितग्राहियों का नाम अभी भी नहीं हटाया गया है। 45 प्रतिशत राशन कार्ड का सत्यापन होने के बार 3,900 हितग्राहियों में कमी आई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि विगत कई वर्षों से शासन को राशन वितरण के नाम चूना लगाया जा रहा है। अभी 55 प्रतिशत हितग्राहियों के फिंगर प्रिंट का सत्यापन शेष है। ऐसे 5,000 से अधिक हितग्राहियों का नाम कम होना लगभग तय है। राशनकार्ड में ऐसे बुजुर्ग, निरूशक्त व दिव्यांगों का नाम है जो सत्यापन के लिए दुकान तक नहीं आ सकते। शासन ने ऐसे हितग्राहियों को नाम्नी बनाने का

अधिकार दिया। राशन कार्ड सत्यापन कराने के लिए नहीं आने वालों में ज्यादातर नाम्नी के माध्यम से राशन लेने वाले हितग्राही हैं। बताना होगा कि जिले में 3,26,967 राशन कार्ड हैं।

इनमें 37,656 एपीएल हितग्राही हैं। एक जनवरी से 31 जुलाई तक जिले में 31,765 नए राशन कार्ड बने हैं। इनमें इस अवधि केवल 302 कार्ड बंद हुए हुए हैं। नए राशन कार्ड में 29ए231 बीपीएल हैं। एक ओर राज्य शासन की ओर से विकास की गाथाएं गढ़ी जा रही वहीं जिले सस्ता राशन पाने वालों की होड़ लगी है। बताना होगा कि ई.केवायसी कराने के लिए निर्देश पहली बार 25 मई को जारी की गई थी। 30 जून तक के वायसी पूरा करने के लिए कहा गया। निर्धारित तिथि तक काम पूरा नहीं होने पर समय सीमा 31 जुलाई कर दी गई। अब जबकि 50 प्रतिशत से भी कम लोगों का सत्यापन हुआ है ऐसे में समय सीमा 31 अगस्त बढ़ा दी गई है।

जिले के 412 ग्राम पंचायत और पांच नगरीय निकायों के 567 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानवार नाम जोड़ने में की गई गड़बड़ी की वजह लोगों को लंबी दूरी तय कर राशन लेने जाना पड़ता है। दादरखुर्द में दुकान होने के बाद भी ग्रामीणों को मानिकपुर राशन लेने जाना पड़ रहा। इसी तरह श्यांग लेमरू, देवपहरी के दुकानों में लोग 10 से 12 किलोमीटर दूरी तय कर सामान लेने पहुंचे हैं। यही वजह है कि दिव्यांग व बुजुर्ग के.वायसी कराने में नाकाम हैं। पारदर्शितापूर्ण राशन वितरण के लिए ई.पास मशीन को तौलयंत्र से जोड़ना जरूरी है। आए दिन मशीन में आने वाली तकनीकी खराबी की वजह राशन वितरण बाधित रहता है। मशीन की खरीदी हैदराबाद के निजी कंपनी से की गई है। स्थानीय स्तर पर सुधार कराने के लिए केवल दो इंजीनियर पदस्थ किए गए हैं। 567 दुकानों में आए दिन मशीन खराब होने की सूचना मिलती है। समय पर राशन नहीं मिलने से हितग्राही हलकान रहते हैं।

जिला खाद्य अधिकारी ने कहा उचित मूल्य दुकानों ई.केवायसी का कार्य जारी है। जहां तक दिव्यांग अथवा बुजुर्गों के दुकान तक नहीं पहुंचने की समस्या है तो उसके लिए गाइडलाइन मांगी गई है। सत्यापन के अभाव किसी भी हितग्राही राशन में कटौती नहीं होगी।

स्टील प्लांट की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने किया विरोध, मौके पर पुलिस बल तैनात

बेमेतरा। नवागढ़ ब्लॉक के झिरिया बिटकुली गांव में प्रस्तावित स्टील प्लांट को लेकर शुक्रवार को जनसुनवाई रखी गई। यह जनसुनवाई दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमकर इसका विरोध किया। क्षेत्र के लोगों द्वारा इस प्लांट का शुरू से विरोध किया जा रहा है। क्षेत्र के 18 पंचायत के किसानों ने प्लांट स्थापना के विरोध में पत्र लिखे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित प्लांट स्थल के आसपास लगभग 300 एकड़ भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधरोपण किया गया है, जो प्लांट बनने से प्रभावित होगा। भूमि पर 3 एकड़ जमीन में नाला बह रहा है, यदि नाले की दिशा बदल गई तो लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि सिंचाई से वंचित हो जाएगी। प्रस्तावित प्लांट के क्षेत्र में लगभग 10 किसानों की जमीन है, प्लांट बनने से यह किसान खेती करने से वंचित हो जाएंगे। वहीं, जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के लोगों को इस जनसुनवाई में शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखने की अपील की गई। जनसुनवाई के पहले मंगलवार को डीएसपी कौशल्या साहू, तहसीलदार परमानंद बंजारे, नायब तहसीलदार जयंत पटले द्वारा ग्रामीणों की बैठक ली गई थी। उपस्थित ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि जनसुनवाई के दिन ग्रामीण अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि जनसुनवाई में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। यह केवल एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

धर्म, प्रकृति व संस्कृति के रक्षक हैं आदिवासी समाज : रंजना साहू

■ **सनातन परंपरा में आदिवासी समाज का योगदान महत्वपूर्ण : उमेश साहू**

धमतरी। जल, जंगल, जमीन के रक्षक प्रकृति प्रेमी ग्राम कसावही के समस्त आदिवासी भाईङ्कबहनों के साथ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू शामिल होकर शुभकामनाएं दिए एवं स्वयं शोभायात्रा में सर पर कलश रखकर विश्व आदिवासी दिवस की सहभागी बनी। इससे पूर्व समस्त समाज पदाधिकारी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विधायक जी को आमंत्रित करने निज निवास पहुंचे, जिसको विधायक ने आशीर्वाद स्वरूप आमंत्रण को स्वीकार किए। विधायक ने ग्राम कसावही में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित भव्य शोभायात्रा में सर्वप्रथम शामिल हुई जहां पर समाज जनों ने पुष्पमाला पहनाकर एवं पारंपरिक रूप से सिर पर गमछा बांधकर स्वागत अतिथि का किए। विधायक ने कहां की प्रकृति के सच?चे सेवक के रूप में जनजाति समुदाय के लोग अनंतकाल से

पारिस्थितिक संतुलन बनाएं रखने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूरे विश्व के आदिवासी समाज को दिवस के रूप में मनाने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई जिसे आज पर्यंत तक विश्व के सभी आदिवासी समुदाय इस दिवस को मना रहे, जो स्वर्णिम है। श्रीमती साहू ने आगे कहा कि मूल्य, कला, भाषा, उत्सव, परंपराएं, नृत्य एवं आदिवासी महापुरुष देश व प्रदेश की अमूल्य धरोहर है, विश्व में धर्म प्रकृति संस्कृति के रक्षक आदिवासी समाज है। गंगरेल मंडल अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने बताया कि सनातन परंपरा में आदिवासी समाज का योगदान महत्वपूर्ण है, आदिवासी समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ व देश के लिए किए गए बलिदानों व अमूल्य कार्यों को सदैव याद किया जाता है। कसावही के आदिवासी समाज के द्वारा अपनी परंपराओं एवं अपनी मांगों से विधायक को अवगत कराएं।

विश्व आदिवासी दिवस पर इस गरिमा में कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमदी मंडल महामंत्री अमन राव, ग्राम पंचायत सरपंच नोमीन साहू, सुमन मण्डावी, रतनलाल कुमर्रा, रूपराम वीके, छबिलाल नेताम, हिंछाराम, जन्माजय, शत्रुघ्न, निरुप ध्रुव, जनक ध्रुव, धनेश ध्रुव, गुलशन ध्रुव, लीलू राम टेकाम, लखन राम वीके, नारद राम, तुलसी बाई, सांवली बाई, दुर्गा बाई, खेदी बाई, उर्मिला बाई, रतनी बाई सहित बड़ी संख्या में समाजिक जन ग्रामीण उपस्थित रहे।

सत्र व जिला न्यायाधीशों का किया फेरबदल व प्रमोशन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की जिम्मेदारी प्रशांत पाराशर की दी गई है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को रायपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। इसी तरह सूरजपुर फैमिली कोर्ट के जज राकेश बिहारी घोरे को बलौदाबाजार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और बेमेतरा फैमिली कोर्ट के जज विजय कुमार होता को दंतेवाड़ा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ज्यूडिशियल अफसरों में संतोष शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, संतोष कुमार तिवारी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, नीलम सिंह बघेल प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर, शहाबुद्दीन कुरैशी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी पाक्सो बलौदा बाजार, हिमांशु जैन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी पाक्सो कवर्धा, मोना चौहान प्रथम सिविल जज वर्ग एक सीजेएम कोंडागांव, प्रियंका अग्रवाल प्रथम अतिरिक्त जज प्रथम सिविल जज वर्ग एक राजनादगांव, लोकेश कुमार तृतीय सिविल जज वर्ग एक मुंगेली, विरेंद्र सिंह प्रथम सिविल जज वर्ग दो बैकुंठपुर शामिल हैं।

इसी प्रकार न्यायाधीश संघरत्ना भतपहरी का पारिवारिक न्यायालय दंतेवाड़ा स्थानांतरित किए गए हैं। निधि शर्मा तिवारी तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, उदय लक्ष्मी परमार रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रायपुर, मधुसुदन चंद्राकर द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बलरामपुर रामानुजगंज स्थानांतरित किया गया है। आदेश में श्रीकांत श्रीवास अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायपुर जिला न्यायालय, जितेंद्र कुमार ठाकुर सिविल जज वर्ग एक को वर्ग एक व सीजेएम जांजगीर-चांपा, जगदीश राम सिविल जज वर्ग-एक एवं सीजेएम बीजापुर, मोनिका जायसवाल, प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक एवं सीजेएम बेमेतरा, अनिल कुमार बारा प्रथम सिविल जज वर्ग एक व सीजेएम जगदलपुर, संतोष कुमार महोबिया, प्रथम सिविल जज वर्ग-एक एवं सीजेएम सुकमा, पुष्पलता मारकंडे सिविल जज वर्ग-एक एवं सीजेएम नारायणपुर, कृष्ण कुमार सूर्यवंशी प्रथम सिविल जज वर्ग एक व सीजेएम कोरबा, वंदना वर्मा प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग- एक एवं सीजेएम कवर्धा स्थानांतरित किए गए हैं।

कवर्धा पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह

कबीरधाम। 15 अगस्त दिन मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आजादी का पर्व मनाया जाएगा। आयोजन की अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त सुबह 8-30 बजे होगा। मुख्य समारोह के आयोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी जिला पंचायत सीईओ को दिया है। इसके अलावा ध्वजारोहण, सलामी गार्ड आफ ऑनर, मुख्य अतिथि द्वारा परेड निरीक्षण के लिए वाहन समेत अन्य आवश्यक व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी को सौंपी गई है।

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को जवानों ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले मार्च पास्ट की रिहर्सल की। मार्च पास्ट में अव्वल प्रदर्शन करने का रिहर्सल किया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के गरिमापूर्ण आयोजन की तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। 1

14 अगस्त को होगी सद्भावना दौड़

खेल व युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अगस्त को सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी जिला खेल अधिकारी एमके गुप्ता ने बताया कि सद्भावना दौड़ शहर के आउटडोर स्टेडियम से सुबह 7 बजे शुरू होगी। ये दौड़ शहर के स्वामी करपात्री स्कूल, सरदार पटेल मैदान, भारत माता चौक, वीर जयस्तंभ चौक, गुरूनानक चौक, बाजार से होते हुए ऋषभ देव चौक, एकता चौक, वीर जयस्तंभ चौक, भारत माता चौक से वापस आउटडोर स्टेडियम पहुंचेगी। उन्होंने जिले के लोगों को सद्भावना दौड़ में शामिल होने अपील किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

तीन नक्सली स्मारक ध्वस्त नक्सल सामग्री बरामद

दंतेवाड़ा। थाना बारसूर एवं मालेवाही क्षेत्रांतर्गत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। गस्त सर्चिंग के दौरान ग्राम कोहकाबेडा, कुवे के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप सामाग्री पैराबम, कैलक्यूलेटर, दवाइयां, दैनिक उपयोगी की सामाग्री एवं नक्सल पत्रिका सहित नक्सल साहित्य बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने ग्राम मंगनार गट्टापारा तथा ग्राम कोसलनार गोडियापारा (गोमटेम) में नक्सली शहीद सप्ताह (28 जुलाई से 03 अगस्त) के दौरान नक्सली जागेश, दीपक की स्मृति में नवनिर्मित तीन नक्सली स्मारक मिला, जिसे डीआरजी के जवानों ने मौके पर ध्वस्त कर दिया है। वहीं थाना कुकड़ाझोर अंतर्गत ग्राम ताडोनार एवं आकाबेड़ा के मार्ग में डी-माइनिंग की कार्यवाही की गई जिस दौरान ताडोनार-आकाबेड़ा के मार्ग में एक कुकर बम वजन करीब 5 किलोग्राम का मिला जिसे बीडीएस टीम द्वारा बरामद कर सुरक्षात्मक मानको का पालन करते हुये विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है।

चेरपाल साप्ताहिक बाजार पहुंचकर डीआईजी व एसपी ने ग्रामीणों से की चर्चा

दंतेवाड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र तुमड़ीगुण्डा, छोटेकरका, पाहुरनार क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा रेंज के डीआईजी कमलोचन कश्यप एवं पुलिस अधीक्षक गौरव राय अ नक्सली गतिविधियों, ग्रामीणों की समास्याओं के संबंध में जानकारी लेने व अंदरूनी क्षेत्र में स्थापित कैंपों/थानों का औचक निरीक्षण एवं जवानों की समास्याओं के साथ हौसला अफजाई हेतु भ्रमण किया गया तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान डीआईजी व पुलिस अधीक्षक चेरपाल के साप्ताहिक बाजार में जनता के बीच जाकर बाजार की व्यवस्था व बाजार में आये अंदरूनी ईलाकों के ग्रामीणों व दुकानदारों से बातचीत व समस्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भी काफी उत्साह के साथ खुलकर संवाद किया। अंदरूनी क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान नक्सली गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली गई।

कोयला खदान के कारण पांच फीट नीचे धंसी जमीन दहशत में ग्रामीण

कोरबा। कोरबा के सीमावर्ती क्षेत्र पसान में जमीन धंसने की घटना सामने आई है। विजय वेस्ट कोयला खदान से करीब एक किमी दूर बीजाडांड गांव के आश्रित ग्राम गोदहिया पंडो बस्ती में गुरुवार रात करीब एक एकड़ जमीन पांच फीट नीचे धंस गई। जमीन धंसने से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। कोल माइंस के कारण जमीन के धंसने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद बस्ती में अफरा-तफरी की स्थिती बनी हो गई। जमीन के धंसने की आवाज सुनकर कारण ग्रामीण दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि जमीन के धंसने के साथ ही जमीन में दरारें भी पड़ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय घटना होने से किसी को नुकसान नहीं हुआ, अगर यही घटना दिन के समय होती तो निश्चित ही जंगल में चरने गए मवेशियों को काफी नुकसान होता। जमीन धंसान की घटना को लेकर खान प्रबंधन को कई बार चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया।

वकीलों ने की अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

कबीरधाम। कबीरधाम जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के अधिवक्ताओं ने दोपहर के समय जिला कोर्ट परिसर से पैदल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कलेक्ट्रेट में मौजूद जिला स्तर के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष कमल साहू, उपाध्यक्ष सीपी राजपूत, सचिव धनीराम साहू ने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगें हैं, जो लंबित हैं। इसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपये करने व सामूहिक जीवन बीमा लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना बेहद जरूरी है। पूर्व में भी इस अधिनियम की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञापन के दौरान जल्द से जल्द मांग पूरी किए जाने का निवेदन किया है।

एसआई की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे पांच लाख

बेमेतरा। बेमेतरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एसआई (सब इंस्पेक्टर) की नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने बिलासपुर के दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में एक आरोपी महिला है। पीड़ित ने वर्ष 2018 में बेमेतरा एसपी के पास लिखित में शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा के सामने आरोपियों ने रुपये वापस किए जाने की बात कर मामले का सेटलमेंट किया था। साथ ही रुपये लिए जाने की बात स्वीकर करते हुए किस्तों में राशि देने का इकरार नामा भी किया था। फिर, आरोपियों ने पीड़ित को 4 साल बाद भी रुपये वापस नहीं किए। पीड़ित ललित मोहन वैष्णव (38) निवासी हाई स्कूल रोड वार्ड नंबर-5 ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी संतोष बंजारे निवासी रमपुरा व मोनिषा सिंह निवासी हेमू नगर, बिलासपुर ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी लगाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी।

विजय देवांगन के नेतृत्व में शहर विकास की नई इबारत गढ़ रही है: सलीम रोकड़िया

धमतरी। नगर निगम क्षेत्र के रमसगरी गार्डन जो शहर के प्रमुख पार्कों में से एक है जहां रोजाना सैकड़ो की संख्या सुबह शाम लोग घूमने आते है. ऐसे में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा हाई मास्क लाइट रमसगरी गार्डन में लगाया जा रहा है. जिसका भूमि पूजन विधि विधान से पूजा पाठ कर नगर निगम महापौर विजय देवांगन,जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष सलीम रोकड़िया,जिला कांग्रेस महामंत्री आलोक जाधव,प्रभारी सदस्य लोकनिर्माण विभाग राजेश ठाकुर,एमआईसी सदस्य राजेश पांडेय,पार्षद ममता योगेश शर्मा,दीपक सोनकर,नीलू पवार के आतिथ्य में संपन्न हुआ।

शहर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षित बनाने नगर पालिक निगम महापौर विजय देवांगन के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है जिसके चलते शहर को स्वच्छ रखने,राष्ट्रीय राजमार्ग बिजली पोल में एलईडी लाइट, घड़ी चौक, मकई गार्डन,पावर हाउस चौक, रत्नाबाँधा चौक सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर धनहा धमतरी, मोर धमतरी, सुघ्घर धमतरी, हमर धमतरी,आई लव धमतरी जैसे अनेक स्लोगन लिखा हुआ एलईडी बोर्ड लगाकर शहर को और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। भूमि पूजन के अवसर पर महापौर विजय देवांगन ने बताया कि रमसगरी गार्डन शहर के मुख्य पार्क में से एक है जिसमें रोजाना सैकड़ो की संख्या में नागरिक घूमने आते है हमारे द्वारा लगातार गार्डन को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है. पार्क में आने वाले लोगों को और सुविधा उपलब्ध प्रदान करने आज हाईमास्क लाइट का भूमि पूजन किया गया है जिससे पार्क आकर्षक बनने के साथ-साथ यहां आने वाले लोगों को सुविधाए प्राप्त होगी. निगम द्वारा शहर के विभिन्न तालाबों का भी सौंदर्यीकरण किया जाना. गर्मी के दिनों में अमूमन शहर के तालाब सुख जाते थे लेकिन हमारे निगम टीम की मेहनत और प्रयास है कि विगत वर्षों से गर्मी के दिनों में जलस्तर बना रहता है. श्री देवांगन ने शहरी क्षेत्र में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वही जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष सलीम रोकडिया ने कहा की निगम में 138 साल बाद विजय देवांगन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस के महापौर बनने के बाद से धमतरी शहर विकास की नई इबारद गढ़ रही है। इस अवसर पर तनवीर कुरैशी, अंबर चंद्राकर, पवन यादव, संजू यादव, संतोष नाग, महेंद्र कुमार, मंगलू निर्मलकर, हेमंत सहारे सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

निर्माणाधीन कांग्रेस भवन के निरीक्षण में पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष

धमतरी। जिला मुख्यालय धमतरी में कांग्रेस कार्यालय निर्माण होने के बाद अब ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालय में भी कांग्रेस भवन का निर्माण किया जा रहा है. इस तारतम्य मे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भखारा कांग्रेस भवन का निर्माण अंतिम चरणों में है. जिसके बाद भखारा कांग्रेस की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां नए कांग्रेस भवन से संचालित होगी निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भरत नाहर के साथ निरीक्षण कर भवन निर्माण पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए श्री लोहाना नहीं बताया कि जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन निर्माण होने के बाद ब्लॉक मुख्यालय में भी कांग्रेस भवन का निर्माण किया जाना है भखारा ब्लॉक कांग्रेस भवन का निर्माण अंतिम चरणों में है।

सरपंच ने आवास दिलाने के नाम पर लिए रुपये वापस मांगने पर ग्रामीण को बंधक बनाकर पीटा

बिलासपुर। बिलासपुर में सरपंच व उसके साथियों द्वारा दबंगई और मारपीट करने का मामला सामने आया है। सरपंच ने ग्रामीण को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सरपंच व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढनढन का है। ढनढन निवाली शिवचरण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सरपंच उमेश ध्रुव को 20 हजार रुपये नगद दिए थे, लेकिन पीएम आवास में उसका नाम नहीं आया। इसके बाद शिवचरण सरपंच से रुपये वापस मांगने लगा। वहीं, सरपंच रुपये वापस करने में आनाकानी करने लगा। बताया जा रहा है कि बीते 8 अगस्त को इसी बात को लेकर सरपंच उमेश ध्रुव अपने साथियों के साथ शिवचरण के पास पहुंचा

और बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की।

इस दौरान लोहे के रॉड, डंडे से आरोपियों ने शिवचरण को खूब मार, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इधर मामले में ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच सहित उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सदन चलता है, प्रधानमंत्री मोदी घूमते रहते हैं : नीतीश कुमार

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल प्रचार में विश्वास करते हैं और पार्टी का आम लोगों के लिए कल्याण कार्य करने का कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री ने मणिपुर जातीय हिंसा पर बयान नहीं देने के लिए नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। मोदी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि नई दिल्ली में संसद चल रही थी और पीएम नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद नहीं थे। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई होगी। अटल जी के कार्यकाल में जब मैं केंद्र सरकार में था तो सभी लोग सदन के अंदर रहते थे। मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सदन (संसद) चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं। क्या पहले ऐसा होता था? इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अब चीजों का केवल एक ही पक्ष दिखाया जाता है। दूसरे जो कहते हैं वह सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखना विपक्ष का अधिकार है और वे ऐसा कर रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग चुप थे वे राजनीति कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर एक दिन पहले लोकसभा में अपने जवाब के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा था जिसके बाद सिब्बल ने मोदी पर यह हमला किया है। मोदी ने कहा था कि विपक्ष को मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री: विपक्ष मणिपुर पर राजनीति कर रहा है। बिल्कुल नहीं। याद है, उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। कहा था कि यह संवैधानिक लोकतंत्र में अस्वीकार्य है।

डेटा संरक्षण बिल का मकसद 'स्थायी रूप से आपातकाल' लागू करना : मोइली

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने पिछले दिनों संसद द्वारा पारित 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2023' को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह कानून प्रतिगामी है तथा यह स्थायी रूप से आपातकाल लगाने' की नीयत से लाया गया है। डेटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2023' को गत बुधवार को संसद ने मंजूरी दे दी। इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डाटा का संवर्द्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। पूर्व कानून मंत्री मोइली ने एक बयान में कहा, ''यह विडंबना है कि सरकार चाहती है कि इस देश के नागरिक और उनका डेटा पूरी तरह से पारदर्शी हों, जबकि सरकार खुद को इस आवश्यकता से पूरी तरह मुक्त रखना चाहती है।''

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। केजरीवाल और सिंह ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित विवाद पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले अपमानजनक बयान दिए। मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर की गई थी। पटेल के अनुसार, केजरीवाल ने 1 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसे अपमानजनक बयान दिए और सिंह ने 2 अप्रैल को दूसरे संवाददाता सम्मेलन में ऐसे बयान दिए। इससे पहले केजरीवाल और संजय सिंह ने पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में पांच सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप पर अपना निष्कर्ष नहीं दे देती। चार राज्यसभा सांसदों ने दावा किया था कि चड्ढा ने 7 अगस्त को एक प्रस्ताव में उनकी अनुमति के बिना उनका नाम शामिल किया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सांसदों की शिकायतों को मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। सांसद सस्मित पात्रा, एस फांगनोन कोन्याक, एम थंबीदुरई और नरहरि अमीन ने चड्ढा पर उनसे पूछे बिना उनका नाम सदन के पैनल में जोड़ने का आरोप लगाया। इस बीच, आप ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चड्ढा को जानबूझकर फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया, कहा-

आईपीसी पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से खत्म कर देगा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा। शाह ने आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। शाह ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आजादी की 100 वर्ष की यात्रा की शुरुआत के साथ अमृत काल का आरंभ होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन में देश के सामने पांच प्रण रखे थे जिनमें एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। अमित शाह लोकसभा में कहा कि आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी), तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड।

उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों के बनाए हुए जितने भी कानून हैं उन पर सोच-विचार और चर्चा करके उन्हें आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाया जाना चाहिए। वहीं से यह प्रक्रिया शुरू हुई। शाह ने कहा कि ये कानून अंग्रेज शासन को मजबूत करने एवं उनकी रक्षा के लिए उन्होंने बनाए थे। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। शाह ने कहा, नए कानून में सबसे पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के

खिलाफ अपराध से संबंधित होगा और दूसरे अध्याय में मनुष्य हत्या के अपराध से जुड़े प्रावधान होंगे।

उन्होंने बताया कि नए कानून में मॉब लिचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के लिए सात साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने राजद्रोह पर कानून बनाया था, लेकिन हम राजद्रोह के कानून को पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं। हालांकि, विधेयक में देश के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। विधेयक की धारा 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार काम करती थी। इन तीन कानूनों के साथ देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा। अमित शाह ने कहा, इन विधेयक का उद्देश्य अदालतों में दोषसिद्धि की दर को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आए हैं कि जो धाराएं सात साल या उससे ज्यादा जेल की सजा का प्रावधान करती हैं, उन सभी के तहत मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य किया जाएगा।

विधेयक में प्रमुख रूप से मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया दंड संहिता, नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए मौत का प्रावधान और सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी शामिल है। अलगाववाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों को अलग-अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का भी प्रावधान लाया गया है। राजद्रोह का अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत कवर किया गया है।

शाह ने कहा कि अब सभी अदालतों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा, प्राथमिकी से लेकर निर्णय लेने तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, अदालतों की समस्त कार्यवाही तकनीक के माध्यम से होगी और आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब राजनीतिक रसूख वाले लोगों को भी किसी तरह छोड़ा नहीं जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, छह केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय सबूत कानून 1872 में संशोधन के लिए एक आपराधिक कानून संशोधन समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर डॉ. रणबीर सिंह को बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्यों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. जीएस बाजपेयी, डीएनएलयू के वाइस चांसलर डॉ. बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशल कोर्ट के पूर्व जज जीपी थरेजा शामिल थे। फरवरी 2022 में इस समिति ने जनता से सुझाव के बावजूद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्य सभा में बताया कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने हमला बोला, कहा-

'जानबूझ कर मणिपुर को जलने दिया वे आग बुझाना नहीं चाहते'

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर उन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपने भाषण के दौरान लगातार हंस रहे थे। मणिपुर में महीनों से आग लगी है। जो मैंने मणिपुर में सुना और देखा वो पहले नहीं देखा। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने संसद में बोला कि प्रधानमंत्री ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था। ये खोखले शब्द नहीं हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या बात है। ये राहुल और कांग्रेस की बात नहीं है बल्कि देश की बात है।

जब हम मणिपुर पहुंचे। जब हम मैतई एरिया में गए। हमें साफ कहा गया था कि आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा। उसको यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। जब हम कुकी के एरिया में गए तो हमें कहा गया कि कोई भी मैतेई आपकी सिक्योरिटी में होगा उसे आप मत लाइए उसे हम गोली मार देंगे। जब हम गए तो हमें मैतेई और कुकी को परे करना पड़ा। आज एक स्टेट नहीं दो स्टेट हैं। स्टेट की हत्या कर दी गई है। उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला कि हिन्दुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कल पीएम मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला। अंत में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री हँस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। यह उन्हें शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते थे, समुदायों से बात कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूं, आइए बात शुरू करें लेकिन मुझे कोई इरादा नहीं दिखता... सवाल यह नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है जहां बच्चे, लोग मारे जा रहे हैं।

राहुल ने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री को हंसते

हुए और मजाक उड़ाते हुए देखा मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो नहीं जा सकते हैं वहां उसके भी कारण हैं। छोड़िए मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है हिन्दुस्तान की सेना उसको दो दिन में रोक सकती है। अगर हिन्दुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो तो दो दिन में ये तमाशा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में विषय मैं नहीं था और ना ही कांग्रेस पार्टी थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का विषय था मणिपुर। लेकिन पीएम ने मणिपुर को फोकस नहीं किया। यह इस बात का प्रमाण है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे पीएम बंद नहीं कराना चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा बंद हो। वे मणिपुर को जलाना चाहते हैं।

राहुल गांधी से जब यह पूछा गया कि उन्हें चर्चा के दौरान काफी कम समय के लिए टीवी पर दिखाया गया इसके बारे में उनका क्या कहना है? इसपर राहुल गांधी ने कहा कि शायद पीएम मोदी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे टीवी पर ज्यादा समय के लिए दिखाया नहीं जाता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चर्चा में मुझे जिस बात को उठाना था मैंने उठाया।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच आज

फ्लोरिडा। भारत ने तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर शानदार वापसी की। इस जीत के साथ भारत ने मौजूदा पांच मैचों की टी20 सीरीज में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। सीरीज को 2-2 से बराबर करने के लक्ष्य के साथ हार्दिक पंड्या की टीम शनिवार 12 अगस्त को फ्लोरिडा के लॉडरहिल में चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों से उम्मीद करेगी कि वे अच्छा प्रदर्शन करते हुए शनिवार को यहां चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और जीत से सीरीज बराबर करने में मदद करें। भारत भले ही तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत से सीरीज में बने रहने में कामयाब हुआ हो लेकिन वेस्टइंडीज अब भी सीरीज में 2 - 1 से आगे चल रही है। मेजबान टीम की बल्लेबाजी इकाई को लेकर चिंता अब भी बरकरार है। सूर्यकुमार यादव को पिछले मैच में अपने आक्रामक रवैये में बल्लेबाजी करते हुए देखना काफी सुखद था और तिलक वर्मा ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन का योगदान किया था। लेकिन भारत की सलामी जोड़ी का लचर प्रदर्शन जारी रहा। ईशान किशन को आराम देकर जायसवाल को टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण कराया था।

भारत-हार्दिक पंड्या (कप्तान), ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार।

वेस्टइंडीज- रोवमैन पॉवेल (कप्तान), काइल मायर्स, जानसन चार्ल्स, शाई होप, रोस्टन चेस, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसफ, ब्रैंडन किंग, ओबेद मैकॉय, निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, ओशाने थॉसम, ओडियन स्मिथ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 366 अंक टूटा निफ्टी 19,450 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिल कमजोर रुझानों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 360 से अधिक अंक टूटा। एनएसई के निफ्टी में भी लगभग 115 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। नेगेटिव ग्लोबल सेंटीमेंट के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महंगाई के पूर्वानुमान में किए गए बढ़ोतरी से भी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 365.53 अंक यानी 0.56 फीसदी की गिरावट के साथ 65,322.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,727.80 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,274.61 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 114.80 अंक यानी 0.59 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,428.30 अंक पर बंद हुआ।

ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स

नईदिल्ली। लोकसभा ने 'केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023' और 'एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023' को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों को मंजूरी लेनी होगी।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा : पुरी

नईदिल्ली। विभिन्न कारोबार से जुड़े समूह आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि भारत ऐसे समय में 'वृद्धि का प्रतीक' बनकर उभरा है जब दुनिया सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। पुरी ने कहा, 'यह ऐसे समय में हो रहा है जब सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि को प्रभावित करने वाले गंभीर समस्याओं से दुनिया जूझ रही है। बहुसंकट और अनिश्चितता के इस माहौल में भारत वृद्धि का प्रतीक बनकर उभरा है और इस साल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।' उन्होंने कहा कि भारत की मजूबत वृद्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों का प्रमाण है। साथ ही पुरी ने कहा कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं (एफएमसीजी) के कारोबार में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

जायडस लाइफसाइंस का नेट प्रॉफिट पहली तिमाही में बढ़ा

नईदिल्ली। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी जायडस लाइफसाइंस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल -जून) तिमाही में नेट प्रॉफिट दो गुना होकर 1,086.9 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में नेट प्रॉफिट 518.3 करोड़ रुपये था। जायडस लाइफसाइंस लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि समीक्षाधीन अवधि में परिचालन आय सालाना आधार पर 29.6 प्रतिशत बढ़कर 5,139.6 करोड़ रुपये रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 3,964.4 करोड़ रुपये थी। भारत में पहली तिमाही में 1,920.6 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 1,816.7 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में अमेरिका में बिक्री में 57.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

बहुत मुश्किल नहीं 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट

अखिलेश प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि वह इस बात को पक्का करेंगे कि उनके तीसरे कार्यकाल में इंडिया की इकॉनमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए और दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाए। अभी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जर्मनी हैं। जीडीपी के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर है। पीएम ने जो कहा है, वैसा होना खास मुश्किल नहीं है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अब से लेकर साल 2030 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 पर्सेंट सालाना रहेगी। इस रफ्तार से 2030 तक भारत का जीडीपी 5 नहीं, बल्कि 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अभी भारत का जीडीपी साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दूसरे देशों से भारत का जो व्यापार है, उसका सबसे ज्यादा योगदान होगा जीडीपी बढ़ाने में। फाइनैंशल ईयर 2023 में एक्सटर्नल ट्रेड 1.2 ट्रिलियन डॉलर का था। यह साल 2030 तक बढ़कर 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है।

इसके बाद ग्रोथ में योगदान होगा देश के भीतर होने वाली खरीद-फरोख्त का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट कहती है कि फाइनैंशल ईयर 2021 में इस हाउसहोल्ड कंजम्पशन का साइज 2.1 ट्रिलियन डॉलर का था, लेकिन वित्त वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 3.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी 2450 डॉलर थी, लेकिन फाइनैंशल ईयर 2030 तक यह लगभग 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी। तब इंडिया की प्रति व्यक्ति आय 4000 डॉलर हो जाएगी। इस तरह इंडिया मिडल इनकम इकॉनमी बन

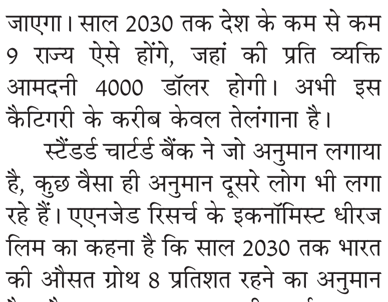

जाएगा। साल 2030 तक देश के कम से कम 9 राज्य ऐसे होंगे, जहां की प्रति व्यक्ति आमदनी 4000 डॉलर होगी। अभी इस कैटिगरी के करीब केवल तेलंगाना है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया है, कुछ वैसा ही अनुमान दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। एएनजेड रिसर्च के इकनॉमिस्ट धीरज लिम का कहना है कि साल 2030 तक भारत की औसत ग्रोथ 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है और तब तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। साल 2030 तक भारत का नॉमिनल जीडीपी 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है।

लेकिन एएनजेड रिसर्च के इकनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि अभी जो हाल है, अगर ऐसा ही बना रहा, तो साल 2030 तक भारत की ऐवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.2 प्रतिशत तक ही रह जाने का खतरा है। यह 2019 तक के 10 वर्षों में दिखी ऐवरेज ग्रोथ से कम होगी। उस दौरान औसत जीडीपी ग्रोथ 7.1 प्रतिशत थी। यही नहीं, 2030 के बाद साल 2050 तक जीडीपी ग्रोथ घटकर 4 प्रतिशत तक जा सकती है। इस लिहाज से एएनजेड रिसर्च के अर्थशास्त्री कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हैं। भारत की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रही है। यानी लेबर फोर्स में 15 से 64 साल की कामकाजी उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी कम हो रही है। खासतौर से महिलाओं की।

वर्ल्ड बैंक का कहना है कि साल 2000 में भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60 प्रतिशत था, जो अब घटकर 53 प्रतिशत के आसपास आ गया है। भारत की वर्कफोर्स पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी काफी पीछे है। बालिग कामकाजी लोग मुश्किल से 6.7 साल की औसत स्कूलिंग वाले हैं। स्किल इंडिया जैसे कदम ठीक हैं, लेकिन इनका दायरा और इनकी क्वॉलिटी बेहतर करनी होगी। भारत की वर्कफोर्स का महज 2.3 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, जिसने स्किल डिवेलपमेंट का कोई औपचारिक प्रशिक्षण लिया है। इन बातों को देखते हुए पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि भारत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसके लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। इंडिया को खेती-बाड़ी से सरप्लस लेबर को मैन्युफैक्चरिंग की ओर लाना होगा। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार में खेती-बाड़ी की हिस्सेदारी 1980 के दशक में 72 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 50 प्रतिशत के आसपास आ गई है।

संसद में विपक्ष का मकसद प्रधानमंत्री का अपमान था!

चंद्र प्रकाश पाण्डेय

मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कई मायनों में अनोखा था। ये एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव था जिस पर खुद उसे लाने वालों को ही 'अविश्वास' था। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता बार-बार ये जिक्र करते रहे कि उन्हें पता है सरकार बहुमत की 'बाहुबली' है लेकिन इसे सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री का 'मौन व्रत' टूट सके। यह केंद्र सरकार के खिलाफ संभवत: ऐसा पहला अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर वोटिंग के वक्त उसे लाने वाले ही सदन में मौजूद नहीं थे। डिविजन की नौबत ही नहीं आई, ध्वनिमत से ही अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। सवाल उठता है कि आखिर इससे विपक्ष को हासिल क्या हुआ? इस अविश्वास प्रस्ताव ने मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की कथित संवेदनशीलता की भी पोल खोलकर रख दी है। उनकी 'अविश्वास प्रस्ताव' की जिद में मणिपुर के लिए संवेदना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के अपमान का भाव था। इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ जब विपक्ष ने किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की अपनी जिद को पूरा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही बाधित करता रहा। उसकी मांग थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बोलें। सरकार भी चर्चा को तैयार थी लेकिन गतिरोध की वजह दोनों पक्षों की जिद थी। जिद नियमों को लेकर। विपक्ष नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की जिद पर अड़ा था तो सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराने की जिद पर अड़ी थी। सरकार बार-बार कह रही थी कि वह तो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर मणिपुर से चर्चा के लिए भागने का आरोप लगा रहा था। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही। लेकिन न सत्ता पक्ष को इससे कोई खास फर्क पड़ रहा था, न विपक्ष को। अचानक विपक्ष ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए चौंकाने वाला दांव खेला। अविश्वास प्रस्ताव का दांव। ये जानते हुए भी मोदी सरकार के पक्ष में प्रचंड बहुमत है, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया ताकि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए 'मजबूर' किया जा सके। विपक्ष को इस दांव का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार भी है लेकिन उसने क्या किया? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। पक्ष-विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। अपने भाषणों में ही गौरव गोगोई और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता कहते रहे कि इसे लाने का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री का 'मौन व्रत' तोड़ना है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जोरदार हमले हुए। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा पर विस्तार से अपनी बात रखी। विपक्ष को राजनीति के बजाय समाधान और शांति की राह में सहयोग करने की अपील की। अगले दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव अपनी बात रखी। विपक्ष अपनी जिद में कामयाब हो चुका था। प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे। जब वह विपक्ष और कांग्रेस पर बेरहम हमले किए जा रहे थे तब विपक्षी सांसद मणिपुर पर बयान की मांग को लेकर नारे लगा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जबतक मणिपुर मुद्दे पर आते, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर तंज भी कसा कि विपक्ष को सिर्फ सुनाने की आदत है, गाली देने की आदत है लेकिन उनमें सुनने का धैर्य नहीं है। पीएम ने अपना भाषण पूरा किया। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करने वाले गौरव गोगोई का नाम पुकारा, चर्चा का जवाब देने के लिए। लेकिन गोगोई तो सदन में मौजूद ही नहीं थे। जिस नेता ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, वही उस पर वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं था। आखिरकार ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। विपक्ष की जिद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बोलें। लेकिन जब उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बोला तो सदन में विपक्षी सदस्य ही नदारद थे। विडंबना देखिए कि जिस जिद के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जब वह पूरा हो रहा था तो विपक्षी सदस्य उस पल का गवाह ही नहीं बने। अगर विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री से बयान चाहता था तो उसे सुनना भी चाहिए था। वॉकआउट से विपक्ष ने आखिर क्या और किस तरह का संदेश दिया? विपक्ष का वॉकआउट बताता है कि मणिपुर पर उसकी कथित संवेदना, कथित वेदना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है।

संसद की पिच पर सत्ता पक्ष का छक्का

नीरज कुमार दुबे

संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने राजनीति की पिच पर सत्ता पक्ष के सामने जो बॉल फेंकी थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छक्का लगा दिया है। वैसे आंकड़ों के लिहाज से यह पहले से तय था कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं है। यही नहीं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से एक दिन पहले ही राज्यसभा में भी विपक्ष की बड़ी हार हो गयी थी जब सत्ता पक्ष ने सदन में अपना बहुमत नहीं होते हुए भी दिल्ली में सेवाओं संबंधी विधेयक को पारित करा लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक हार के तुरंत बाद विपक्ष दूसरी हार का स्वाद चखने को क्यों आतुर था? देखा जाये तो इस प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान से मिल जाता है। प्रधानमंत्री ने संसद में पिछले अविश्वास प्रस्ताव के समय कहा था कि कांग्रेस ने इस संवैधानिक प्रावधान का सर्वाधिक बार दुरुपयोग किया है। देखा जाये तो इस बार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया वह भी एक तरह से संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग ही था क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाया गया कदम था। प्रधानमंत्री ने तो कहा भी है कि पिछली बार भी और इस बार भी फ्लोर टेस्ट सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का ही था।

लोकसभा में तीन दिन की बहस में सबसे अच्छा भाषण किसका रहा, किसने किसको धो डाला, किसका भाषण सबसे खराब था या किसका भाषण औसत दर्जे का था, इन सब मुद्दों की चर्चा से पहले हमें यह देखना चाहिए कि इस बार की बहस के दौरान क्या नया रिकॉर्ड बना है? हम आपको बता दें कि जो नया रिकॉर्ड बना है वह है हर पक्ष के वक्ताओं की ओर से एक दूसरे पर निजी हमले बोलने का। यह निजी हमले जिस तरह बेहद निजी हमलों में परिवर्तित हुए वह दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके अलावा, पांच साल पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक सदस्य द्वारा आंख मारी गयी थी तो इस बार सदन में उनकी फ्लाइंग किस का किस्सा सामने आया।

विपक्ष के नेताओं के भाषणों का विश्लेषण

संसद में पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आये हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन जैसे विपक्षी नेता सत्ता पक्ष पर हमले के लिए निचले स्तर पर कभी नहीं उतरे थे। उस समय माहौल ऐसा होता था कि सत्ता पक्ष से ज्यादा लोग विपक्ष के प्रमुख नेताओं के भाषण सुनने को आतुर रहते थे क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर ही अपनी बात गरिमापूर्ण तरीके से रखते थे। लेकिन इस बार विपक्ष ने जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण दिये और प्रधानमंत्री पर तीखे हमले किये, वह अभूतपूर्व था। विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने भले शानदार शुरुआत की और मणिपुर को लेकर अपनी पार्टी की चिंताओं को प्रमुखता के साथ देश के समक्ष रखा लेकिन विपक्ष के अन्य नेता कनिमोझी, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, टीआर बालू, अरविंद सावंत, सिमरनजीत सिंह, एनके प्रेमचंद्रन, महुआ मोइत्रा आदि कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाये। इसके अलावा, विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी और मनीष तिवारी के भाषणों में तर्कों और अनुभव की झलक थी लेकिन अधीर रंजन और राहुल गांधी ने कई विवादित बातें कह कर सत्ता पक्ष को और हमलावर होने का मौका दे दिया। इसके साथ ही जदयू के राजीव रंजन सिंह हों, शिरोमणि अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल हों, एआईएमआईएम के असद्दुदीन ओवैसी हों, बीजद के पिनाकी मिश्रा हों, नेशनल कांफ्रेंस के फारुक अब्दुल्ला हों, निर्दलीय नवनीत राणा हों, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान हों, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल हों या वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिधुन रेड्डी हों...इन सबका भाषण भी स्थानीय राजनीति और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया।

दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषणों को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पक्ष पर भारी पड़े। अपने सारगर्भित संबोधन के जरिये उन्होंने देश को हर सवाल का जवाब दिया और अपनी पार्टी को आगामी चुनावों में जीत के लिए भी तैयार कर दिया। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को रखा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि देश से जुड़े हर मुद्दे का तर्कपूर्ण जवाब दिया और विपक्ष की ओर से फैलायी जा रही भ्रांतियों को भी दूर किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन भी काफी व्यापक रहा। एक तो वह उसी पूर्वोत्तर से आते हैं जहां मणिपुर स्थित है, दूसरा वह अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के प्रति सत्तारूढ़ दल के रुख और सरकार की पूर्वोत्तर नीति को लेकर निशाना साधता है इसीलिए रिजिजू का संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सरकार की आर्थिक नीतियों और उसके प्रभाव को लेकर विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखा। अन्य मंत्रियों में स्मृति ईरानी का संबोधन राजनीतिक भाषण की दृष्टि से काफी प्रभावी रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अच्छा बोले लेकिन वह अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस पर ही ज्यादा निशाना साधते दिखे। नारायण राणे और साध्वी निरंजन ज्योति जैसे मंत्री कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाये। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, निशिकांत दुबे जैसे सत्तारुढ़ पक्ष के वक्ता औसत ही रहे। लॉकेट चटर्जी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों खासकर बंगाल से जुड़े विषयों को लेकर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे का संबोधन शानदार रहा। उन्होंने दर्शा दिया है कि वह उद्धव गुट के उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे के मुकाबले ज्यादा प्रभावी वक्ता हैं।

तीन दिनों तक चली इस बहस का निचोड़ देखेंगे तो यही सामने आता है कि सभी नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक हित साधे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस ने उनका भाषण कराके अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। इसके अलावा, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से वक्ता के रूप में लोगों का चयन करते समय चुनाव से जुड़े हितों को ही ध्यान में रखा। देखा जाये तो सभी पार्टियों के नेता साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले खुद की तैयारियों को परखना चाहते थे इसलिए सबने अपने भाषण को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने का काम किया। देखा जाये तो राजनेताओं के भाषणों को उनके समर्थकों ने सराहा, लाइक किया और शेयर किया। लेकिन सवाल उठता है कि इससे देश को और मणिपुर को क्या मिला? देश चाहता था कि संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा हो कि महंगाई को कैसे कम किया जाये, बेरोजगारी को कैसे कम किया जाये, साम्प्रदायिक सद्भाव के बिगड़ते माहौल संबंधी घटनाओं को कैसे काबू में लाया जाये, भ्रष्टाचार को कैसे पूरी तरह खत्म किया जाये, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर कैसे लगाम लगायी जाये, ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर कैसे तत्काल रोक लगाई जाये...लेकिन इसमें से किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। यानि जनता के जो मुद्दे थे वो वहीं के वहीं रह गये।

बहरहाल, विपक्ष इस बात पर अपनी जीत मना रहा है कि वह प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर बोलने के लिए मजबूर करने में सफल रहा। सरकार इस बात पर अपनी जीत मना रही है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। यानि दोनों पक्ष अलग-अलग तरह से अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन इस सारे शोर में हार तो संसदीय प्रणाली की हुई है क्योंकि विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र का अधिकांश समय हंगामा करके बर्बाद कर दिया जिससे जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाये। यही नहीं, सत्र दर सत्र लगातार हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के सरकार को विधेयक पारित कराने की अब आदत पड़ गयी है। विधेयकों पर चर्चा नहीं होने से जनता को अपने लिये बन रहे कानून के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यही नहीं, जिस मणिपुर को लेकर यह सारा राजनीतिक हंगामा हुआ उस पर चर्चा के बहाने से सभी दलों ने एक दूसरे के कार्यकाल में हुए दंगों और हिंसा से जुड़े घटनाक्रमों का उल्लेख कर पुराने जख्मों को कुरेदा। खैर...लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का जो प्रस्ताव पारित किया है वह काफी सकारात्मक कदम है। यदि इस चर्चा के माध्यम से ही मणिपुर में शांति कायम हो जाये तो एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों की ही बड़ी जीत होगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

नारायणोपनिषद

यह लघुकाय उपनिषद् कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इसे नारायणाथर्वशिर उपनिषद् भी कहा जाता है। इस उपनिषद् में चारों वेदों का उपदेश सार शिर (मस्तक) के रूप में वर्णित है। सर्वप्रथम नारायण से ही समस्त चेतन-अचेतन के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् नारायण की सर्वात्मकता (सभी की आत्मा के रूप में) का विवेचन है। तदुपरान्त नारायण के अष्टाक्षर मंत्र (नमो नारायणाय) की विवेचना है। इसके पश्चात् नारायण और प्रणव (कार की ऐक्यता तथा अन्त में इस उपनिषद् के अध्ययन करने का प्रतिफल बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि इस लघुकाय (संक्षिप्त) उपनिषद् के अध्ययन करने से चारों वेदों के पाठ का पुण्यलाभ प्राप्त हो जाता है।

उन पुरुषरूप भगवान् नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा (जीवों) की सृष्टि करूँ। अत: उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई। भगवान् नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं सम्पूर्ण जगत् को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान् नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। नारायण से भगवान् रुद्र उत्पन्न होते हैं। नारायण द्वारा ही देवराज इन्द्र प्रकट हुए। नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए। ग्यारह रुद्र, अष्टवसु एवं सम्पूर्ण छन्द भगवान् नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान् नारायण में ही अन्त में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद् का कथन है। भगवान् नारायण ही नित्य (शाश्वत) हैं। ब्रह्माजी भी नारायण हैं। भगवान् शिव एवं देवराज इन्द्र भी नारायण हैं। काल और दिशाएँ भी नारायण हैं। विदिशायें (दिशाओं के मध्य के कोण) भी नारायण हैं। ऊर्ध्व भी नारायण और अध: भी नारायण है। अन्त: एवं बाह्य भी नारायण हैं जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है, वह सभी कुछ भगवान् नारायण ही हैं। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरञ्जन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है, वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है, ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद् का कथन है। सर्वप्रथम आरम्भ में कार का उच्चारण करे, तदुपरान्त बाद में नम: शब्द का और फिर अन्त में नारायण पद का उच्चारण करे।

क्रमश: ...

राकेट और उपग्रह निर्माण की बुनियाद रखी थी विक्रम साराभाई ने

विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को जन्म दिया और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नींव डाली। उन्होंने राकेट, उपग्रह निर्माण और उपग्रहों के उपयोग संबंधी देश के भावी कार्यक्रम को दिशा दी। भारत का चंद्रमा पर पहला अभियान चंद्रयान उसी आधारभूत योजनाओं की उपज है। रूस और अमेरिका जैसे देश विश्वयुद्ध के दौरान सामरिक तकनीक के कारण राकेट और उपग्रह निर्माण की दिशा में अग्रणी थे।

भारत को आजादी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में शुरुआत करनी थी। साराभाई ने न सिर्फ राकेट और उपग्रह निर्माण की बुनियाद रखी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह सेवाओं के उपयोग की दशा तथा दिशा तय की। 12 अगस्त 1919 में गुजरात के अहमदाबाद में एक धनी परिवार में जन्मे साराभाई सपने देखते थे और उसे क्रियान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत पर विश्वास करते थे। वह एक महान दृष्टा थे। वह महान वैज्ञानिक मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी से बहुत प्रेरित थे। गुजरात कालेज से इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा पास करने के बाद वह 1937 में ब्रिटेन पढ़ने चले गये।

दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद वह भारत आ गए तथा उन्होंने बंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में डॉ. सीवी रमन की देखरेख में कास्मिक किरणों पर अनुसंधान कार्य शुरू किया। उनका पहला शोध पत्र कास्मिक किरणों के समय वितरण से संबंधित था जो उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी के कार्यक्रम में पेश किया।

विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद साराभाई ब्रिटेन लौटे और भौतिकी में अपना अनुसंधान पूरा करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की। भारत में टेलीविजन को विकासात्मक संचार का साधन बनाने की परिकल्पना साराभाई ने की थी। दूरदर्शन के शुरुआती परीक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ब्लूप्रिंट साराभाई ने ही बनाया था। 1975-76 में नासा के सहयोग से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट से इसे संचालित किया गया। भारत के छह राज्यों और 2500 से अधिक गांवों में टीवी प्रसारण किया गया।

डॉ. विक्रम साराभाई को 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक' के रूप में जाना जाता है। महान वैज्ञानिक के तौर दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले विक्रम साराभाई ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। विक्रम साराभाई को एक संस्थान निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है। कम्युनिटी साइंस सेंटर और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आदि की स्थापना कराने में भी विक्रम साराभाई का बड़ा योगदान माना जाता है। विक्रम साराभाई के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था।

साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग (इसरो) के प्रथम अध्यक्ष थे। साराभाई ने जिस पहली संस्था की बुनियाद रखी वह अहमदाबाद की टेक्सटाइल अनुसंधान केंद्र थी। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय प्रबंधन संस्थान और कम्युनिटी साइंस केंद्र की स्थापना की। साराभाई विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में बहुत विश्वास रखते थे। इसके लिए उन्होंने अहमदाबाद में कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की। जनवरी 1966 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। वह भारत में फार्मास्युटिकल अनुसंधान के क्षेत्र के अग्रणी समर्थक थे। 30 दिसंबर 1971 को केरल के कोवलम में साराभाई का निधन हो गया।

केजरीवाल के अहंकार का खामियाजा दिल्ली भुगत रहा

ललित गर्ग

आखिरकार केजरीवाल सरकार के अधिकार सीमित करने वाला दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। सोमवार को राज्यसभा में बिल के समर्थन में 131 व विरोध में 102 वोट पड़े। बहरहाल, अब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत कानून का रूप ले लेगा। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की मनमानी, भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं पर नियंत्रण लगाने के लिये इस बिल को सफलतापूर्वक पारित कर लिया है, इससे विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस की भी हार एवं किरकिरी हुई है। आम आदमी पार्टी की जिद, अहंकार एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोकतंत्र के मंदिर 'संसद' में संविधान के सामने परास्त हो गई। क्योंकि संविधान केवल अधिकार नहीं देता, शुद्ध आचरण की अपेक्षा भी करता है। नि:सन्देह यह भाजपा सरकार की ऐतिहासिक जीत इसलिये है क्योंकि पहले कयास लगाये जा रहे थे कि राजग के सभी सहयोगियों के वोट मिलने के बावजूद केंद्र सरकार राज्यसभा में बिल को पारित नहीं करवा पायेगी। वह भी तब जब एक-दूसरे पर लगातार हमलावर रहने वाले आप व कांग्रेस समेत इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लुसिव अलायंस 'इंडिया' के सभी घटक दल बिल के खिलाफ एकजुट हो चुके थे।

दरअसल, लोकसभा में बहुमत होने के चलते राजग सरकार ने बिल आसानी से पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने ने उसकी चिंता बढ़ा दी। ऐसे वक्त में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल तथा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने राजग की नैया पार लगा दी। निश्चित रूप से यह 'इंडिया' गठबंधन की बड़ी नाकामी है। भ्रष्टाचार एवं अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के कारण इस तरह की पराजय नये भारत के लिये जरूरी भी है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविन्द केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिये दिल्ली की जनता के प्रति निरन्तर संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया है, जिसका खामियाजा उनको प्राप्त अधिकारों के पर कतरने के रूप में सामने आया है, और इन्हीं कारणों के चलते यह संशोधन लाना पड़ा है।

केंद्र सरकार के 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' पर आम आदमी पार्टी और उसके साथ खड़े सभी राजनीतिक दलों को मुंह की खानी पड़ी। याद रखें कि आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया था। आप के सर्वेसर्वा एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी गैर-भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्रियों एवं भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों से बिल पर समर्थन जुटाने के लिए 'भारत भ्रमण' तक कर लिया था।

दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि वह लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ दे। इसके बाद भी आप पार्टी के हाथ जब कुछ नहीं आया, तो उसके नेताओं ने अन्य अनैतिक एवं अलोकतांत्रिक रास्ते भी अपनाने का प्रयास किया। राज्यसभा में आप के सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। सत्ता पक्ष के पांच सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में उनके नाम डाले गए, जिसे हद दर्जे की मनमानी, फर्जीवाड़ा और अपराध मानते हुए इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाने की मांग की गयी, उपसभापति हरिवंश ने इसकी जांच की बात कही है। संभव है इस पर आप के सांसद राघव चड्ढा को सजा हो। दिल्ली सरकार में तरह-तरह के भ्रष्टाचार एवं जालसाजी के किस्से आम बात हो गयी थी, विडम्बना है कि देश की भोलीभाली जनता को इन भ्रष्टाचारों को भाजपा की चाल करार देकर सहानुभूति जुटाने में माहिर आप सरकार ने संसद को भी नहीं बख्शा। संसद के भीतर जालसाजी के आरोपों में फंसी आप पार्टी ने खेद प्रकट करने की जगह कार्रवाई के डर से, अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाजपा अब उसके सांसद राघव चड्ढा के पीछे पड़ गई है। यह तो वही बात हुई कि 'एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी'। यदि राघव चड्ढा सही हैं, उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तब उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को डरने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? आप पार्टी एवं उसके नेता केजरीवाल की राजनीति एवं सोच विकृत है, उनका व्यवहार झूठा है, चेहरों से ज्यादा नकाबें उन्होंने ओढ़ रखे हैं, उन्होंने सारे लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक मूल्यों को धराशायी कर दिया है। ऐसी मूल्यहीन राजनीति के चलते देश के भविष्य को लेकर करोड़ों लोग चिन्ता एवं ऊहापोह में हैं। वक्त आ गया है कि देश की राजनीतिक संस्कृति की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिये सतर्क एवं सावधान होना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व के सामने नये मानदण्ड रखने होंगे। जो राजनीतिक दल फर्जीवाड़े एवं भ्रष्टाचार को सामान्य मानते हैं, उन्हें आइना दिखाना होगा। हर कहीं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो और उजागर होने पर माफी मांगकर आगे बढ़ जाओ की विकृत सोच, चालाकी एवं अवसरवादी राजनीति पर नियंत्रण करना होगा। संभवत: दिल्ली सर्विस बिल का संसद में सफलतापूर्वक पारित होना, इस दिशा में एक सार्थक पहल है, एक सबक है, एक सन्देश है कि सावधान हो जाओ देश को गुमराह करने वालो, लूटने वालों। राजनैतिक वितंडावाद को ही राजनीति समझने वाले आप के नेताओं को समझना चाहिए कि संसद जैसा मंच इस प्रकार की ओछी, संकीर्ण एवं स्वार्थी हरकतों के लिए नहीं है। संसद के किसी भी पटल पर, कोई भी बात गंभीरता से, जांच-पड़ताल करने के उपरांत ही रखनी चाहिए।

हिन्द स्वराज

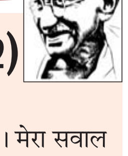

कांग्रेस और उसके कर्ता-धर्ता (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न- ठहरिये, ठहरिये आप तो बहुत आगे बढ़ गये। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज्य की बात करता और आप पर राज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राहपर आये, ऐसा नहीं दीखता। मुझे तो स्वराज्य की ही बातें अच्छी लगती है। दूसरी मीठी सयानी बातोसे मुझे संतोष नहीं होगा।

उत्तर- आप अधीर हो गये है। मैं अधीरपन बरदाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती यह कहावत याद रखिये। आपने मुझे रोका और आपको हिन्द पर उपकार करने वालों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती, यह बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज्य दूर है। आपके जैसे बहुतसे हिन्दुस्तानी हों, तो हम (स्वराज्य से) दूर हटकर पिछड़ जायेंगे। यह बात जरा सोचने लायक है।

प्रश्न- मुझे तो लगता है कि ये गोल-मोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिन्दुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता; फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिन्द के दादा कहते हैं, उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिल-मिलकर रहना चाहिए।

उत्तर- मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से वो बोलना हमारे लिए शरम की बात है। उनके कामों की ओर देखिये। उन्होंने अपना जीवन हिन्द को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिन्द का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, यह सिखाने वाले माननीय दादाभाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं।

क्रमश: ...

द्रविड़ नाडु के विचार पर मोदी का करारा जवाब

नई दिल्ली। आज राज्य क्या है? इंडिया शब्द का हम पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत का हम पर कब प्रभाव पड़ा है? मैं एक खुला बयान दे रहा हूं। हम पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं। हमारा प्रभाव कहां पड़ा? कोई असर नहीं हुआ। भारत उत्तर भारत में कोई जगह है। हम तमिलनाडु से हैं। यदि संभव हो तो हमें एक द्रविड़ नाडु बनाना होगा। हमारी विचार प्रक्रिया उसी दिशा में जा रही थी। यह तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता ईवी वेलु का बयान है। वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा जिसे राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा साझा किया गया है।

मोदी का वार

मामला संसद में भी पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने दो दिन पहले कहा है कि इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। मोदी ने कहा, '' आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धारा निकली है। जिस राज्य ने कामराज, एमजीआर, अब्दुल कलाम दिये। लेकिन आज उस तमिलनाडु से इस प्रकार का स्वर..।'' वहीं, कांग्रेस पर प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि इनके डीएमके के एक साथी ने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत है, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो आकर इसका खंडन करें।

द्रविड़ नाडु का मामला क्या

द्रमुक सरकार अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों से असहमति दिखाती है और केंद्र पर भारत के संघीय ढांचे का पालन नहीं करने का आरोप लगाती थी। इससे पहले नीलगिरि से द्रमुक सांसद ए राजा ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को अधिक स्वायत्तता नहीं दी, तो डीएमके एक अलग राज्य की मांग को फिर से उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। उन्होंने ट्वीट भी किया, मुख्यमंत्री अन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें पेरियार के रास्ते पर मत धकेलें। हमें अपना देश मांगने के लिए मजबूर न करें, हमें राज्य की स्वायत्तता दें। तब तक हम आराम नहीं करेंगे।

द्रविड़ नाडु का विचार?

ई वी रामासामी पेरियार (1879-1973) ने तमिलों की पहचान और आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए आत्म-सम्मान आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र द्रविड़ मातृभूमि द्रविड़ नाडु की परिकल्पना की और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी, द्रविड़ कज़गम (डीके) की शुरुआत की। 1938 में, पेरियार ने पूरे भारत में हिंदी (सीखने) की अनिवार्य शुरुआत की योजना के खिलाफ तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। दावा किया जाता है कि जस्टिस पार्टी की तरह द्रविड़ार कषगम भी ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी और आर्यन विरोधी (उत्तर भारत विरोधी) विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। ब्रिटिश राज के दौरान 1917 में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम की एक पार्टी बनाई गई, जिसे जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1938 में ही पेरियार ईवी रामासामी के आत्मसम्मान आंदोलन के साथ इसका विलय हुआ। द्रविड़ार कषगम लगातार द्रविड़नाडु की मांग करती रही।

अन्नादुराई का उदय

मतभेदों की वजह से सीएन अन्नादुराई (टीएन के पूर्व मुख्यमंत्री) पेरियार से अलग हो गए और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की स्थापना की। इस नए विकास के साथ द्रविड़ नाडु की मांग फीकी पड़ गई। दावा तो यह भी होता है कि पेरियार जहां स्वतंत्र द्रविड़ देश की मांग कर रहे थे तो ठीक इसके उलट अन्नादुरई की मांग केवल अलग राज्?य को लेकर ही थी। यही कारण है कि आजादी के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी को तमिलनाडु नाम दिए जाने पर अन्नादुरई ने द्रविड़नाडु की मांग को छोड़ दिया था। 1967 में अन्नादुरई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे।

1980 के दशक में, एक छोटे उग्रवादी संगठन, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी ने द्रविड़ नाडु की मांग को पुनर्जीवित किया, जब भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) को श्रीलंका भेजा गया था। अब भी समय-समय में डीएमके की ओर से इसकी मांग उठाई जाती है। तमिलनाडु के राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्रों में राज्य की स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखते हैं।

अखिलेश कभी शिवपाल की कीमत नहीं समझेंगे : आदित्यनाथ

लखनऊ। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग चांदी के चम्मच में खाने के आदि हैं। सपा में शिवपाल के साथ अन्याय हुआ है। अखिलेश कभी शिवपाल की कीमत नहीं समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की स्थिति अच्छी है। सपा के राज में सांड बूचड़खाने में होते थे। हमारे राज में सांड पशुपालन का हिस्सा हैं।

सीएम योगी ने कहा कि जब बाढ़ और सूखे पर चर्चा की बात आई तो उसका विषयांतर करने की कोशिश की है। आप जिस सांड की बात कर रहे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। आपने जो अखबार की कटिंग पेश की है उसमें लगता है शिवपाल जी ने कुछ कटिंग आपनी रख दी है। शिवपाल जी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमारी संवेदना उनके साथ है।

सीएम योगी ने कहा कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन हम देखेंगे तो 15 से 20 जून के अंदर मानसून प्रवेश कर जाता था, हमारे अन्नदाता उसके हिसाब से ही तैयारी करते हैं। इस वर्ष मानसून की जो स्थिति है वो प्रदेश के अनुकूल नहीं है। आज आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां काफी कम बारिश हुई है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिम के कुछ जिलों में अतिरिक्त पानी की बात सामने आई है लेकिन वह स्थिति भी ठीक नहीं है। हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इसके लिए मीटिंग की और इस पर रणनीति बनाई ।सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ के कारण फसलों को जो नुकसान पहुंचा उसके आकलन का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश, देश का ऐसा भूभाग है जहां का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई की सुविधाओं के लिए अनुकूल है। धान की नर्सरी लग चुकी है। सरकार अपने स्तर पर इस पर काम कर रही है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक किसानों को मदद कर सकें।

चुनाव आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद, कांग्रेस ने किया विरोध

नईदिल्ली। चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने की मांग करने वाले विधेयक की विपक्ष की आलोचना के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को तत्कालीन भाजपा संसदीय दल का 2012 का एक पत्र साझा किया। पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसी नियुक्तियों के लिए व्यापक आधार वाले कॉलेजियम का सुझाव दिया था। पत्र में आडवाणी ने मांग की थी कि सीईसी और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पांच सदस्यीय पैनल या कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और कानून मंत्री शामिल हों। आडवाणी ने 2 जून 2012 को लिखा था कि मौजूदा प्रणाली जिसमें चुनाव आयोग के सदस्यों को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोगों में विश्वास पैदा नहीं करता है। मनमोहन सिंह ने बाद में कहा कि वह चुनाव सुधारों के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव के लिए तैयार हैं। सुधारों पर सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता के एक पत्र का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि मैं यह बताना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इस्तीफे और हटाने की प्रक्रिया, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है... यह लंबे समय से अस्तित्व में है...प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के लिए...अन्य राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हुआ तो इसे चुनावी सुधारों के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में लिया जा सकता है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक न केवल आडवाणी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ है, बल्कि 2 मार्च, 2023 को 5-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले को भी पलट देता है। सरकार द्वारा प्रसारित विधेयक के अनुसार, चयन तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और दो सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी पार्टी के नेता, एक कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

अधीर रंजन के निलंबन के खिलाफ इंडिया का मार्च

- **राहुल भी रहे मौजूद, खड़गे का सरकार पर निशाना**

नईदिल्ली। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूर रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि वे लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं और संविधान के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि, सभी दलों के हम सभी लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उनके अवैध कार्यों के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हम संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ेंगे।

लोकसभा में हंगामा

फिलहाल लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन और मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने चौधरी के निलंबन का विषय उठाने का प्रयास किया। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह कहते सुना गया कि चौधरी ने आसन के साथ हमेशा सहयोग किया है। शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कहा। लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा।

भाजपा का वार

लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के बारे में पूछे जाने पर, रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पीएम को गाली देना और उनके बारे में गलत बातें कहना सही नहीं है। इस निलंबन के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया जाना चाहिए। वे गलतियाँ कर रहे हैं और फिर दिखाने के लिए वे खुद अच्छे हैं, वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैंने उन्हें(अधीर रंजन चौधरी) उसी समय कहा कि माफी मांगें और खेद व्यक्त करें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया...यह फैसला करना स्पीकर पर निर्भर करता है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संसद में उच्च पद पर बैठे नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करना और चेतावनी के बाद भी बिना माफी मांगे माने लगातार ऐसा करना ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन भारत का संविधान रहेगा। देश में गरिमा और दूसरे नागरिक के प्रति प्रेम और सम्मान ही लोकतांत्रिक देश की पहचान है।

खालिस्तानी कट्टरपंथ की टूटेगी कमर! ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान

नई दिल्ली। खालिस्तानी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए भारत की अपील पर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने नए फंड का एलान किया है। गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन पहले ही कट्टरपंथ से लड़ने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स के गठन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी।

भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री टुगेनहाट के बीच हुई मुलाकात में टुगेनहाट ने नई फंडिंग का एलान किया है, जिससे खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथ से निपटने में ब्रिटेन की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। 95 हजार पाउंड (करीब एक करोड़ रुपए) के निवेश से ब्रिटेन सरकार को खालिस्तान समर्थक उग्रवाद को समझने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त कट्टरपंथ टास्क फोर्स के गठन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री टुगेनहाट तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत दौरे पर आए हैं। भारत द्वारा लगातार ब्रिटेन के सामने खालिस्तान कट्टरपंथ का मामला उठाया जा रहा था। दरअसल ब्रिटेन में हाल के सालों में खालिस्तानी कट्टरपंथ तेजी से उभरा है। भारत की चिंता है कि ब्रिटेन में खालिस्तान उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। भारत की चिंताओं के बीच ही ब्रिटेन की सरकार ने फंडिंग का एलान किया है। टुगेनहाट ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, हमारे बहुत से साझा अवसर हैं, जिनसे दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाया जा सकता है।

जी20 बैठक में होंगे शामिल

ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों देश मिलकर सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि टुगेनहाट को कोलकाता में होने भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तर वाले जी20 सम्मेलन में भी शिरकत करनी है। इस पर टुगेनहाट ने कहा कि भ्रष्टाचार हमारी समृद्धि, हमारे समाज और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है। मैं इस मुद्दे पर भारत में होने वाली जी20 बैठक में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। टुगेनहाट सीबीआई मुख्यालय का दौरा भी करेंगे और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगे।

चंद्रयान-3 के बाद रूस का लूना-25 लॉन्च, इसरो ने दी बधाई

नई दिल्ली। भारत के बाद अब रूस ने भी लूनर मिशन लूना-25 लॉन्च कर दिया है। 47 साल बाद रूस ने अपना यान भेजा है। शुक्रवार को लॉन्च किए जाने वाले इस चंद्रयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी को बधाई दी। इसरो ने यह भी कामना की कि चंद्रयान-3 और लूना-25 दोनों मिशन अपने लक्ष्य हासिल करें। इसरो ने कहा कि लूना-25 के सफल लॉन्च पर रोस्कोस्मोस को हमारी तरफ से बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक और मुलाकात होना अद्भुत है। उसने कहा कि चंद्रयान-3 और लूना-25 मिशनों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं। बता दें, रोस्कोस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है।

शुक्रवार को लॉन्च किए जाने वाले लूना-25 मिशन के बारे में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने भी पुष्टि की है। इससे पहले रोस्कोस्मोस ने साल 1976 में लूना-24 को लॉन्च किया था। 47 साल बाद रूस ने अपना यान भेजा है। मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर पूर्व में स्थित अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 की लॉन्चिंग की गई। कहा जा रहा है कि भारत के चंद्रयान-3 से पहले रूस का लूना-25 चांद पर कदम रखेगा।

रूसी मीडिया के अनुसार, शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 4.40 बजे रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना- 25 लैंडर की लॉन्चिंग की। लूना- 25 को सोयुज 2.1 बी रॉकेट में चांद पर भेजा गया है। इसे लूना-ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। रॉकेट की लंबाई करीब 46.3 मीटर है, वहीं इसका व्यास 10.3 मीटर है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस का कहना है कि लूना-25 चांद की ओर निकल चुका है। पांच दिनों तक यह चांद की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद 313 टन वजनी रॉकेट 7-10 दिनों तक चांद का चक्कर लगाएगा। उम्मीद है कि 21 या 22 अगस्त को यह चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 21 या 22 अगस्त को यह चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। वहीं, चंद्रयान-3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लूना- 25 और चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का समय करीब-करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा।

चुनाव से पहले वतन लौटेंगे नवाज शरीफ पीएम शहबाज शरीफ ने दिया संकेत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके भाई एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने लंबित अदालती मामलों का सामना करने और आम चुनाव को लेकर पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने के लिए अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे। नवाज शरीफ (73) नवंबर 2019 से ब्रिटेन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं।

उन्हें 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह अल-अजीजिया मिल्स मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे थे, इसी दौरान उन्हें 2019 में ''चिकित्सा आधार'' पर लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। गुरुवार को 'जियो न्यूज' के साथ एक साक्षात्कार में 71 वर्षीय शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में कार्यवाहक सरकार के कार्यभार संभालते ही वह अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाएंगे।

शहबाज शरीफ ने दोहराया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करती है तो उनके बड़े भाई चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब निर्धारित अवधि से तीन दिन पहले बुधवार को नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के साथ कार्यवाहक सरकार की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई।

नवाज शरीफ की वापसी की सटीक तारीख बताए बिना शहबाज शरीफ ने कहा, ''नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे और चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे।'' संपत्ति छुपाने के आरोप में 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। दोषसिद्धि के विरुद्ध उनकी अपीलें वर्तमान में संबंधित अदालतों में लंबित हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''वह (नवाज शरीफ) न तो टोपी पहनेंगे और न ही बाल्टी पहनेंगे।'' इमरान खान अदालत में सुनवाई के लिए बुलेटप्रुफ हेलमेट पहनते हैं।

पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी अगला आम चुनाव जीतेगी और वह नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। नेशनल असेंबली के शीघ्र भंग होने से पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को 60 दिनों के बजाय 90 दिनों के भीतर देश में आम चुनाव कराने की अनुमति मिल जाएगी, जो संसद का कार्यकाल पूरा होने के लिए निर्धारित समय है। चुनाव में कुछ महीनों की देरी होने हो सकती है क्योंकि नए जनगणना परिणामों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे चुनाव से पहले परिसीमन करना एक संवैधानिक दायित्व बन गया है। ईसीपी 120 दिनों के भीतर परिसीमन करने और फिर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बाध्य है।

कांग्रेस पर हमलावर होकर क्या गठबंधन में बड़ी दरार डाल गए मोदी!

आशीष तिवारी

सदन में अपने दो घंटे से ज्यादा के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नाम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही घेरा। मोदी का कांग्रेस पर यह हमला तब सबसे ज्यादा आक्रामक था जब तमाम दलों के गठबंधन के साथ विपक्षी दलों ने अपना बड़ा गठबंधन इंडिया बनाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही विपक्ष के नाम पर कांग्रेस को नहीं घेरा है। इसके कई सियासी मायने हैं। उन तमाम सियासी मायनों में एक सबसे बड़ा पहलू यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी दलों में कांग्रेस को सबसे बड़ा बताकर अन्य प्रमुख विपक्षी दलों को कांग्रेस की तुलना में कमजोर साबित किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान मणिपुर से लेकर देश के अन्य तमाम राज्यों में होने वाली अस्थिरता पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नाम पर सबसे पहले कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीन रंजन चौधरी पर कटाक्ष के साथ शुरुआत की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला। राहुल गांधी के हरियाणा के किसानों से खेतों में हुई मुलाकात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर परिवारवाद से लेकर दरबारबाद का भी आरोप लगाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब नॉर्थईस्ट से लेकर केरल और दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सों में विपक्ष को घेरने की कोशिश की तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को ही सबसे आगे रखा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस को ही सामने रखे जाने से एक साथ भारतीय जनता पार्टी के कई सियासी तीर भी छोड़े जा रहे थे। ताकि विपक्ष के नाम पर सिर्फ कांग्रेस का ही नाम सामने आए।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एन सुदर्शन कहते हैं कि विपक्ष के नाम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को घेरे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के बड़े गठबंधन में भी सेंधमारी करने का एक बड़ा सियासी दांव चला है। उनका कहना है इसके एक साथ कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहला तो यह कि अगर प्रधानमंत्री की ओर से विपक्षी दलों के बड़े गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस को ही सबसे आगे प्रमुखता से रखा जाएगा तो अन्य दलों की हैसियत को कमतर साबित करने का एक प्रयास होगा। ऐसी दशा में विपक्षी दलों की एकता में टूट भले ना पड़े लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा होने की संभावना जरूर रहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं विपक्षियों के बीच में सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेसी ही मानी जाएगी।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने सभी राजनैतिक दल खुद को न सिर्फ महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं बल्कि इस बात की भी अंदर खाने में उठापटक मची रहती है कि उनका दल गठबंधन में निचले पायदान पर ना समझा जाए। राजनीतिक जानकार इंद्रेश चतुर्वेदी कहते हैं जब सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस दौरान गठबंधन के कई दलों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनके नेताओं के दस्तखत क्यों नहीं करवाए गए। चतुर्वेदी कहते हैं कि यह चर्चाएं पहले भी होती रहीं है कि कहीं इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस बाजी ना मार ले जाए। इसलिए अन्य दलों के नेता लगातार न सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष आगे रखते आ रहे हैं बल्कि कांग्रेस भी इस बात को समझते हुए अन्य दलों को पूरी तवज्जो दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने दिए जाने वाले अभिभाषण में विपक्षी दलों के अंदर खाने चल रहे इस मिजाज को न सिर्फ भली-भांति परखा बल्कि उस पर सियासी शॉट भी लगा दिया।

सियासी जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो घंटे से ज्यादा चले भाषण का सार अगर समझा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि मोदी ने अपने समूचे अभिभाषण का अपनी सरकार की उपलब्धियां से लेकर कांग्रेस को निशाने पर लेने का भरपूर उपयोग किया। राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते है कि जब बुधवार को अमित शाह की ओर से मणिपुर मामले में विस्तार से सब कुछ सदन बताया गया तो अनुमान यही लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब मणिपुर मामले में फिर वह सब दोहराया नहीं जाएगा। सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती अभिभाषण के दौरान विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया और विपक्ष के नाम पर कांग्रेस सबसे ज्यादा निशाने पर रही। हालांकि कांग्रेस को निशाने पर लेने के मामले में जटाशंकर सिंह का मानना है कि क्योंकि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक देश पर शासन किया है, इसीलिए जब पुराने मामलों का जिक्र होता है तो कांग्रेस का ही नाम सबसे पहले आता है।

बजरंगबली के 12 नामों में है असीम शक्ति

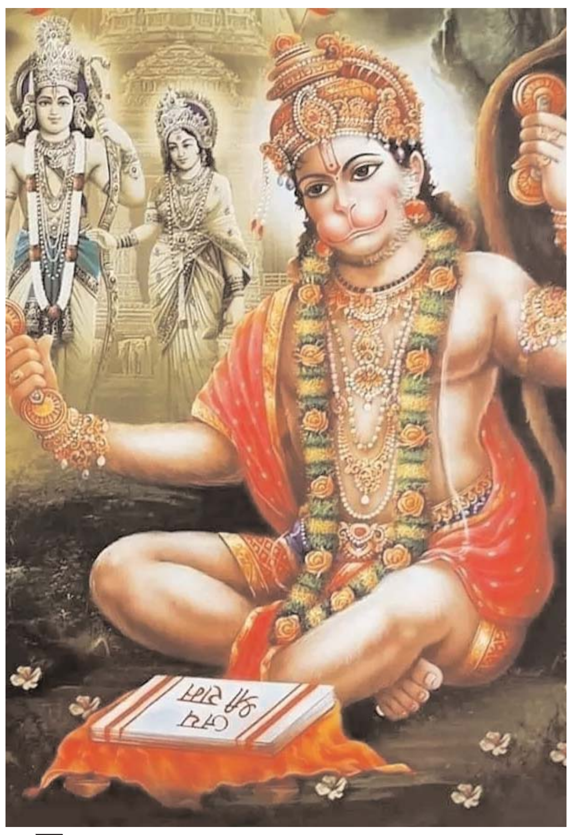

बजरंगबली के 12 नाम का स्मरण करने से ना सिर्फ उम्र में वृद्धि होती है बल्कि समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमानजी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश-पाताल से रक्षा करते हैं।

1. ऊँ हनुमान
2. ऊँ अंजनी सुत
3. ऊँ वायु पुत्र
4. ऊँ महाबल
5. ऊँ रामेष्ठ
6. ऊँ फाल्गुण सखा
7. ऊँ पिंगाक्ष
8. ऊँ अमित विक्रम
9. ऊँ उदधिक्रमण
10. ऊँ सीता शोक विनाशन
11. ऊँ लक्ष्मण प्राण दाता
12. ऊँ दशग्रीव दर्पहा

12 नामों से होने वाले लाभ

1. प्रातःकाल सो कर उठते ही जिस अवस्था में भी हो बारह नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है।

2. नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है।

3. दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है।

4. रात्रि को सोते समय नाम लेने वाले व्यक्ति की शत्रु से जीत होती है।

5. उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन बारह नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमानजी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं।

[भविष्यफल]

मेष

आज आपके पास पर्याप्त समय होने पर भी व्यस्त ही रहेंगे। योगा, प्राणायाम अवश्य करें। लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे।

वृष

आप आज ख़ुद को रोज़ाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा काम के नीचे न दबाएँ, थोड़ा आराम करें।

मिथुन

आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुँचा सकते हों। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं।

कर्क

घर की जरुरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं।

सिंह

अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा-स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की ज़रूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट को जन्म दे सकती है।

कन्या

आज आपका दिन मनोनुकूल रहेगख। शारीरक लाभ मिलेगा। अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है।

तुला

आज का दिन फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगे। धार्मिक रूचि बढेगी।

वृश्चिक

आज आपका ऊर्जा से भरपूर, ज़िंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आस-पास के लोगों को ख़ुश कर देगा।

धनु

मौज-मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता

मकर

आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। खुद के लिए समय निकालें।

कुंभ

आज आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य आपके सकारात्मक रुख़ से प्रभावित होंगे और उसे सराहेंगे।

मीन

अपनी शारीरिक चुस्ती-फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं।

अस्त ग्रह के अशुभ परिणाम क्या होते हैं ?

सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह की संज्ञा प्राप्त है और उसका कारण सूर्य का तेज होता है। वैदिक ज्योतिष के कई महत्वपूर्ण सूत्र है और अस्त ग्रहों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दरअसल कोई ग्रह जब सूर्य के इतना निकट चला जाए की वो सूर्य के तेज और ओज से प्रभावहीन हो जाए तो ऐसे ग्रह को अस्त ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि वो शुभ फल नहीं देता हैं। ऐसे ग्रह कुपित ग्रह कहलाते हैं और माना जाता है कि इनकी दशा अंतर्दशा में इनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य के अलावा बाकी सभी ग्रहों के अस्त होने का दोष लगता है जिनकी जानकारी निम्नलिखित है।

कोई भी ग्रह कब अस्त होगा ?

चन्द्रमा 12 अंश पर, मंगल 7 अंश पर, बुध 13 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर और शनि 15 अंश पर अस्त होते हैं यानी कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य की परिधि में इतने अंश तक आ गया तो वो अस्त हो जाता है। जैसे शुक्र 8 डिग्री का और सूर्य 14 डिग्री का एक ही भाव में हो तो दोनों में सिर्फ 6 डिग्री का अंतर आया यानी कि वो अब अस्त ग्रह हो गया। अब ऐसा ग्रह अपने कारक का शुभ फल प्रकट नहीं कर पाता है। हालांकि बुध सदैव सूर्य के समीप ही रहता है इसलिए कहा जाता है कि बुध के लिए 3 डिग्री को माना जाना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ है और उससे 15 डिग्री के फासले पर है तो वो

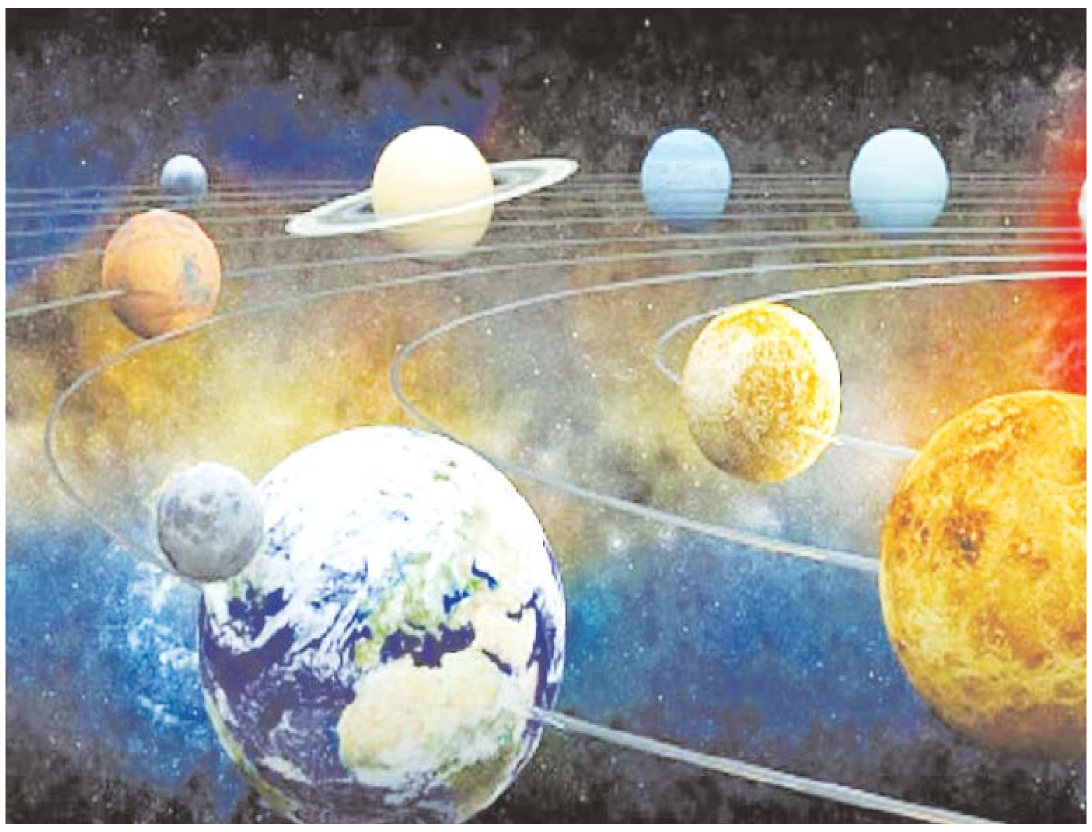

पूर्ण उदित हुआ और अगर फासला सिर्फ 8 डिग्री का है तो वो मध्यम हुआ और अगर फासला 7 डिग्री से कम है तो ऐसा ग्रह बुध को छोड़कर पूर्ण अस्त कहा जाता है।

अस्त ग्रह का फल क्या होता है ?

चन्द्रमा – ऐसा सिर्फ अमावस के समय ही होगा। अगर चन्द्रमा अस्त हुआ तो जातक को मां के सुख में कमी और संपत्ति मिलने में देरी होगी।

मंगल – अगर मंगल सूर्य से अस्त हुआ तो साहस में कमी और प्रॉपर्टी से फायदा नहीं होगा। जिस भी धंधे में जायेगा नुकसान ही होगा।

बुध – इस ग्रह को अस्त होने का दोष नहीं होगा फिर भी ये देखा गया है कि अस्त होने के बाद यह ग्रह कोई खास लाभ नहीं देता है। त्वचा विकार और सम्मान की हानि होती है।

गुरु – अगर गुरु सूर्य से अस्त हो जाए तो चरित्र पर लाछन लगते है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को सदैव सच्चा साबित करने की कोशिश करता रहता है। ज्ञानी होने के बाद भी उच्च पद नहीं मिलता है।

शुक्र– अगर कुंडली में शुक्र अस्त हुआ तो काम पूरे होने में बाधा आती है। पत्नी सुख में कमी और यौन रोग की सम्भावना होगी। ऐसा व्यक्ति लम्पट होता है।

शनि – अगर किसी जातक की कुंडली में शनि अस्त हो तो सरकारी कार्यो में बाधाएं आती हैं। जितना पैसा आएगा उससे अधिक चला जाएगा। सदैव सम्मान की कमी महसूस होगी।

क्या अस्त ग्रह शुभ फल देते है ?

जी हां ! शोध यह कहता है कि अगर किसी जातक की कुंडली के छठे, आठवे और द्वादश भाव के स्वामी अस्त हो तो जातक को शुभ परिणाम मिलता है। यानी की वो प्रभावहीन होकर उस भाव के अशुभ फल प्रकट नहीं करता है। जैसे अगर गुरु शुभ भाव का स्वामी हो और अस्त हो वो अपने कारक यानी पुत्र, धन, स्वर्ण प्राप्ति में समस्या देगा लेकिन वही गुरु अगर अशुभ भाव का स्वामी होकर अस्त हुए तो जातक को उस भाव के अशुभ परिणाम नहीं देंगे और जातक को आसानी से उस भाव से जुडी अच्छी चीजें मिल जायेगी। एक तरह से यह विपरीत राजयोग जैसा फल हो जाता है।

सफलता के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं ये लोग

सामान्य स्थितियों में व्यक्तियों के हाथ में केवल एक ही सूर्य रेखा मिलती है, लेकिन बहुत कम हाथों में एक से अधिक सूर्य रेखाएं भी मिलती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि हाथ में एक ही सूर्य रेखा है और यह हृदय रेखा को काटते हुए मस्तिष्क रेखा तक पहुंचे तो यह सरकारी नौकरी का योग बताती है। यदि सूर्य रेखा छोटी हो और हृदय रेखा से पहले ही रुक जाए तो मनचाही नौकरी पाने में सफलता मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। यह स्थिति असफलता का संकेत देती है। यदि सूर्य पर्वत पर दो समानान्तर सूर्य रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में आय के दो स्त्रोत होते हैं। इस स्थिति में ज्यादातर लोग जॉब के साथ बिजनेस करते हैं।

यदि सूर्य पर्वत पर तीन या चार रेखाएं हैं अथवा ये सभी आपस में उलझी हुई हैं तो यह व्यक्ति को असमंजस में डालती हैं। ऐसे लोग कोई काम शुरू करते हैं और जल्द ही इनका मन उस काम से उचट जाता है। ज्यादा उलझी हुई सूर्य रेखाएं कॅरियर में मुश्किलों को बढ़ाती हैं। ऐसे लोगों को सफलता के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के लोगों को सोच समझकर किसी काम में हाथ डालना चाहिए। यदि हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा हो, साथ ही सूर्य और शनि की उंगली के बीच से कोई रेखा निकलते तो वे राजनीति में सफलता हासिल करते हैं।

घर की इस दिशा में भूल से भी न लगाएं घड़ी

जानें इसे लगाने के सही वास्तु नियम

इंसान के जीवन में घड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। घड़ी न सिर्फ हमें समय बताती है, बल्कि हमारे अच्छे-बुरे समय में भी योगदान देती है। वास्तु शास्त्र में भी घड़ी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु जानकारों के अनुसार यदि घर में सही दिशा में घड़ी न लगी हो या फिर खराब पड़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही तमाम कोशिशों के बावजूद काम नहीं बनते हैं और प्रत्येक काम में बाधा आती है। वहीं जब आप वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर की दीवार पर सही दिशा में घड़ी लगाते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और अटके कार्य भी पूरे होने लगते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं घड़ी से जुड़े सही वास्तु नियम...

घर में भूलकर भी न रखें ऐसी घड़ी

वास्तु के अनुसार घर में कभी भी खराब या बंद घड़ी न रखें। साथ ही ऐसी घड़ी भी दीवार पर न लगाएं, जिसका शीशा टूटा हुआ हो। टूटी या बंद घड़ी को घर में रखने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक असर पड़ता है। कहा जाता है कि रुकी हु घड़ी की तरह परिवार के सदस्यों की प्रगति भी रुक जाती है, इसलिए यदि घड़ी की बैटरी खत्म हो गई हो तो उसे तुरंत बदल दें।

किस दिशा में लगाएं घड़ी?

अक्सर लोग घड़ी को अपनी सुविधा के अनुसार घर की किसी भी दीवार में टांग देते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं होता है। कुछ खास स्थान और दिशा हैं, जहां घड़ी लगाने से शुभ परिणाम मिलते हैं। वास्तु जानकारों की मानें तो उत्तर और पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा माना गया है। ऐसे में घर की इन्हीं दिशाओं की दीवार पर घड़ी लगाएं।

इस दिशा में भूलकर भी न लगाएं घड़ी

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर से नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में यदि आप इस दिशा में कोई घड़ी लगाते हैं तो समय देखने के लिए बार-बार आपका ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है।

कैसी हो घड़ी की आवाज?

अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों की आवाज कर्कश होती है, जो तनाव देने वाली होती है। आपके घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम रहे इसके लिए हमेशा मधुर ध्वनि वाली घड़ी ही लगाएं।

घर की छत पर भूलकर भी न रखें यह सामान

आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का कारण

जीवन में तरक्की और उन्नति के लिए वास्तु नियम का पालन जरूरी है। लापरवाही बरतने से जीवन में कई परेशानियों का समाना करना पड़ता है। इसके लिए लोग गृह निर्माण से लेकर प्रवेश तक वास्तु नियमों का पालन करते हैं। साथ ही वास्तु के अनुसार, घर की चीजों को उचित स्थान पर रखते हैं। हालांकि, जब बात छत की आती है, तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छत पर अनावश्यक चीजों को रखने से वास्तु दोष लगता है। यदि आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के साथ घर से कलह को दूर रखना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बताए गए उपायों को करते हुए घर की छत को पूरी तरह से साफ-सुथरा रखें। वैसे भी बुजुर्ग लोगों व धर्माचार्यों का कहना है कि घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, माना जाता है कि रात के वक्त देव गण पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जिससे वे उसी छत पर उतरते हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है। आप भी घर की सुख और समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं तो तो घर की छत पर गलती से भी ये सामान न रखें-

छत पर न रखें झाडू

अक्सर लोग घर की साफ सफाई करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लोग घर को साफ रखते हैं, लेकिन छत की साफ-सफाई करना भूल जाते हैं। कई लोग गलती से घर के छत पर झाड़ू रख देते हैं। अगर आप भी घर के छत पर रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। इससे आर्थिक तंगी आती है।

रस्सी का बंडल न रखें

अक्सर लोग छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं। हालांकि, छत पर रस्सी रखने से वास्तु दोष लगता है। इसके लिए छत पर रस्सी का बंडल न रखें। हां, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांध सकते हैं।

छत पर न रखें बाँस

वास्तु शास्त्र में छत पर बांस रखना शुभ नहीं होता है। इसके लिए छत पर बांस न रखें। अगर छत पर बांस रखते हैं, तो घर की सुख और समृद्धि गायब हो जाती है।

जमा न होने दें कचरा

कई लोगों के घर के आसपास पेड़ होते हैं। इनसे पत्ते गिरकर छत पर जमा होने लगते हैं। इसके लिए नियमित अंतराल पर छत की सफाई करें। छत पर कचरा जमा रहने से वास्तु दोष लगता है।

टूटे गमले व मटके न रखें

कुछ लोगों को टूटे गमले या मटके को छत पर रखने की आदत होती है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लगता है। इसके लिए कचरे को कभी छत पर न करें।

टूटे फूटे सामान, रद्दी, पुराने अखबार से दूर रहें

इसके अलावा, घर के छत पर रद्दी, पुराने अखबार, जंग लगा सामान, लकड़ी के टूटे फर्नीचर आदि चीजें न रखें। इन चीजों को छत पर रखना शुभ नहीं होता है। अगर आप भी घर की सुख और समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं, तो वास्तु के इन नियमों का जरूर पालन करें।

संक्षिप्त समाचार

संकल्प शिविर में भाग लेने आज आएंगे सप्तगिरि

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सप्तगिरि शंकर उल्का 12 अगस्त शनिवार को दोपहर 1.45 बजे माना विमानतल पहुंचकर रांवाभाठा, रायपुर ग्रामीण विधानसभा के लिये रवाना होंगे। दोपहर 2.30 बजे मां बंजारी गुरुकुल विद्यालय परिसर, रांवाभाठा पहुंचकर आयोजित रायपुर ग्रामीण विधानसभा के संकल्प शिविर में भाग लेंगे। दोपहर 3 बजे रांवाभाठा से शहीद स्मारक भवन रायपुर के लिये रवाना होंगे। दोपहर 3.30 बजे शहीद स्मारक भवन पहुंचकर आयोजित रायपुर दक्षिण विधानसभा के संकल्प शिविर में भाग लेंगे।

शिवसेना का त्रिशूल यात्रा 14 को

रायपुर। शिवसेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में 14 अगस्त को लाखेनगर चौक से महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ तक त्रिशूल यात्रा निकाली जाएगी। जहां 11 फीट का त्रिशूल भगवान शिव को अर्पण किया जाएगा। शिवसेना के द्वारा यह परंपरा पिछले 30 वर्षों से निभा रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े, रायपुर जिला सचिव हिमांशु शर्मा व प्रदेश सचिव संजय नाग ने बताया कि शिवसेना के द्वारा सावन माह के दौरान 1997 से रायपुर में त्रिशूल यात्रा निकाला जा रहा है और एक त्रिशूल भगवान हटकेश्वरनाथ को अर्पण किया जा रहा है। इस वर्ष भी 14 अगस्त को त्रिशूल यात्रा निकाली जाएगी जिसमें राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों के कार्यकर्ता लाखेनगर चौक में एकत्रित होंगे और वहां से एक साथ हटकेश्वर नाथ के लिए 11 फीट का त्रिशूल लेकर कार्यकर्ता निकल पड़ेंगे। जहां भगवान शिव को त्रिशूल अर्पण कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की जाएगी।

मिशन अमृत-2 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की छठवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के छह शहरों की जल प्रदाय योजनाओं की विस्तार से चर्चा के उपरांत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति दी गई। इन जल प्रदाय योजनाओं से करीब 26 हजार 603 से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल प्रदाय परियोजनाओं की लागत करीब 354 करोड़ रूपए होगी। बैठक में मिशन अमृत-2 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार स्टेट एक्शन प्लान को भी अनुमोदित किया गया। बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतिकरण के जरिए मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत पांच शहरों की जल प्रदाय योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने जांजगीर-चांपा के शिवरीनारायण, कोण्डागांव जिले की कोण्डागांव, कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर, जशपुर जिले की कुनकुरी, सुकमा जिले की सुकमा और धमतरी जिले की आमदी जल प्रदाय योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया कि अमृत मिशन एक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया है, इनमें ज्यादातर योजनाओं के कार्य पूर्णता की ओर है। अमृत मिशन के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने पर केन्द्र सरकार द्वारा 69 करोड़ 77 लाख रूपए की रिफार्म इंसेंटिव छत्तीसगढ़ को प्रदाय किया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल राजधानी रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। प्रदेश में 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। इसी तरह उप मुख्यमंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव सरगुजा, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे बेमेतरा, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत राजनांदगांव, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया बालोद, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल रायगढ़, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम कोण्डागांव, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा सुकमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार मुंगेली तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया जांजगीर-चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन दंतेवाड़ा, संसदीय सचिव श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर महासमुंद, संसदीय सचिव डॉ. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह बिलासपुर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी कांकेर में ध्वजारोहण करेंगे।

अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने से फायदा होगा : कांग्रेस

रायपुर। वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। चुनाव से ऐन पहले नेताम के इस कदम से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। अब आदिवासी समाज किसी राजनीतिक दल को समर्थन देगा, यह सवाल भी खत्म हो गया है क्योंकि आदिवासी अब खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इसी रणनीति के तहत आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। नेताम ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए दिया है जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह प्रदेश नेतृत्व का रवैया बताया है।

अरविंद नेताम की आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ है। वे आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वालों के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी समाज में उनका अच्छा मान सम्मान भी है। कई बार आदिवासी के मुद्दों को लेकर अरविंद नेताम अपनी ही पार्टी से भिड़ गए या फिर अपनी पार्टी की गाइडलाइन से अलग होकर उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी। जिस वजह से कई बार उन्हें पार्टी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वे आदिवासियों को लेकर काम करते रहे हैं।बड़े आदिवासी नेता के चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने को लेकर कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि अरविंद नेताम के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को काफी फायदा होगा। ये काम उन्हें पहले कर लेना चाहिए था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा बहुत देर कर दिया उन्होंने। वह भानुप्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे। जो अपने पार्टी के खिलाफ में काम करता है वह अपने आप निष्कासित हो जाता है। इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी विरोधी गतिविधि में सम्मिलित थे। भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं। उनकी बैठक भी लगातार हो रही है। लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उनका निष्कासन नहीं किया। कितने बार वे दल बदल चुके हैं। पहले निकाल लेते तो अभी तक एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची। जिसमें नेताम ना गए हो, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है। उनके जाने से नुकसान नहीं उल्टा फायदा होगा।

आदिवसी वोटर्स के लिए बस्तर के चक्कर लगा रही भाजपा ने कांग्रेस से आदिवासी नेता के इस्तीफे को लपक लिया और एक बार फिर कांग्रेस में आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। भाजपा इस बात से खुश है कि अरविंद नेताम के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से आदिवासी वोटर भाजपा की तरफ झुकेगा।

भाजपा के अनुराग अग्रवाल ने कहा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ता है तो उसमें नुकसान कांग्रेस को ही होगा। वरिष्ठ नेता ने आदिवासी दिवस के दूसरे दिन कांग्रेस छोड़कर बता दिया कि इस सरकार से आदिवासी कितने नाराज हैं। जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है सिर्फ आदिवासियों को कठपुतली की तरह उपयोग हो रहा है। जब भी कोई अपने अधिकारों का बात करते हैं तो वह अपने पद से हटा दिया जाते हैं। चाहे मोहन मरकाम हो प्रेमसाय सिंह टेकाम हो। आदिवासियों की नाराजगी अब सामने आने लगी है।

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई का कहना है कि अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अरविंद नेताम कांग्रेस में पहले से ही साइड लाइन थे। उनकी कोई पूछ परख नहीं थी। लेकिन आदिवासियों के बीच उनकी एक अच्छी छवि है, काफी पुराने आदिवासी नेता हैं।आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को इसका खास नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। भाजपा को भी इससे बहुत फायदा नहीं पहुंचेगा। कुछ हद तक आदिवासी वोट प्रभावित होंगे जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट हैं।

रवि भोई ने कहा नेताम की पार्टी कोई सीट जीत पाए, इसकी उम्मीद कम ही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक सिर्फ दो पार्टियों का ही अस्तित्व रहा है। वह कांग्रेस और बीजेपी है। 1-2 सीट पर बसपा जीतती है। 2018 में जोगी पार्टी अपने दम पर कुछ सीट जीती थी। इसलिए कह सकते हैं कि नेताम थर्ड फ्रंट बनने की स्थिति में नहीं है।

अरविंद नेताम कांग्रेस से पांच बार कांकेर से सांसद रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अरविंद नेताम को कृषि राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद ही बस्तर में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई थी। तब से नेताम कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन साल 2012 में अरविंद नेताम को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया, क्योंकि नेताम ने राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी की जगह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और आदिवासी लीडर पीए संगमा को समर्थन दिया था। जनवरी 2017 में अरविंद नेताम ने बीजेपी से निष्कासित पूर्व सांसद सोहन पोटाई के साथ जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी। इसके बाद राहुल गांधी ने जन स्वराज सम्मेलन में नेताम की एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कराई।

अब एक बार फिर नेताम ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। लेकिन इस बार नेताम किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं बल्कि सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इस बार आदिवासी समाज सीधे चुनाव लड़ेगा ना की किसी बैनर तले मैदान में उतरेगा।

नेताम चार बार सांसद, दो बार मंत्री बने, फिर भी पार्टी का साथ छोड़ा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। हाल ही में अरविंद नेताम ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। इसके बाद से ही भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। इधर, कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर दौरे पर आए कांग्रेस के प्रभारी मंत्री मोहन मरकाम ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोरिया दौरे के दौरान मरकाम से मीडिया ने नेताम के पार्टी छोड़ने पर प्रश्न किया। इस पर मरकाम ने कहा कि पार्टी में उन्हें सम्मान दिया है फिर भी वे पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, इसका कारण वे ही बता सकते हैं।

मोहन मरकाम ने कहा कांग्रेस पार्टी ने नेताम को सम्मान दिया है। पार्टी ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। दो बार वे मंत्री बने। उनके परिजनों को भी टिकट दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसका कारण तो नेताम ही बता सकते हैं। सीएम का जनता से किया वादा हो सके पूरा-मोहन मरकाम

दो दिवसीय दौरे पर एमसीबी गए हैं। वह सीएम की ओर से किए गए विकास कार्यों पर किस तरह काम हुआ है? अभी कितना विकास कार्य अधूरा पड़ा है? इसकी समीक्षा बैठक में जानकारी लेकर उन सभी कार्यों को जल्द पूरा करने की प्रक्रिया किया जाना है। ताकि चुनाव के समय तक मुख्यमंत्री का जनता से किया वादा पूरा हो सके विधायकों का होता है सर्वे- कहीं बीजेपी से नंद कुमार साहू के आने के कारण तो अरविंद नेताम ने पार्टी नहीं छोड़ा? इस सवाल के जवाब में मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

आप के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान चुनावी सर्वे में 2 दर्जन से अधिक विधायक खतरे में हैं। बता दें कि कांग्रेस की ओर से समय-समय पर विधायकों और मंत्रियों का सर्वे कराया जाता है। उसके आधार पर ही टिकट दिया जाता है।

भूपेश बघेल का भाजपा पर आरोप, लोगों की भावनाओं से खेल रही भाजपा

रायपुर। रायपुर में शुक्रवार को भूपेश बघेल मिनीमाता स्मृति दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम बघेल के साथ प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के मेरी माटी मेरा देश अभियान पर सवाल उठाया। बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव आते ही बीजेपी भावनात्मक खेल खेलती है। जनता भाजपा के खेल को जान चुकी है।

रायपुर के शहीद स्मारक भवन में शुक्रवार को मिनीमाता स्मृति दिवस का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के समय पहली महिला सांसद के तौर पर पहचान रखने वाली मिनी माता की पुण्यतिथि पर उनको याद किया।

भूपेश बघेल ने कहा मिनीमाता की ओर से समाज के गरीब और दबे लोगों के लिए किए गए कामों को याद करके उनको याद ताजा हो गई। मिनी माता ने कई बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह अविभाजित मध्य प्रदेश के समय पहली महिला संसद के तौर पर पहचान रखती थी। प्लेन क्रैश की घटना में मिनीमाता का निधन हो गया। भाजपा %मेरी माटी मेरा देश% के तहत लोगों की भावनाओं से खेल रही है। जनता भाजपा के खेल को समझ गई है।

रायपुर में मिनीमाता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर सतनामी समाज की सामाजिक पत्रिका का विमोचन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। सतनामी समाज की ओर से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले महिला और पुरुषों को सम्मानित भी किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में मिनीमाता की ओर से किए गए कामों को याद किया गया।

अरुण वोरा ने सीएम भूपेश बघेल को बताया भोले बाबा

- **भाजपा बोली कोई इंसान नहीं बन सकता भगवान, टिकट पाने की है लालसा**

दुर्ग। सावन का महीना चल रहा है। मंदिरों शिवालयों में भोले बाबा के भक्त उन पर अपनी अटूट श्रद्धा जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भोले बाबा को लेकर ऐसा बयान दिया कि विपक्ष तिलमिला उठा। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दल पूरी ताकत के चुनावी मैदान में उतरने से पहले तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपना खाता खोलने के लिए बरकरार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों स्थानीय मुद्दों को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा का निवास घेरा। इस घेराव को दौरान जब मीडिया ने अरुण वोरा से प्रदर्शन का कारण पूछा तो उन्होंने आप और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल की तुलना भोले बाबा से कर दी। बस फिर क्या था जिस विपक्षियों को अरुण वोरा के इस बयान की जानकारी जैसे लगी माहौल गर्म हो गया।

आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद जब अरुण वोरा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बात हो रही थी।उसी दौरान अरुण वोरा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके घर के अंदर बने मंदिर में आने को कहा।अरुण वोरा ने कहा कि भोले बाबा के दर्शन कर लिजिए। लेकिन समस्याओं की सुलझाने की मांग को लेकर आप पार्टी के नेताओं ने अरुण वोरा की बात नहीं मानीं। इसके बाद जब मीडिया ने अरुण वोरा से सवाल किए तो वोरा ने कहा जिस तरह से भोले बाबा पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रहे हैं।

अरुण वोरा ने कहा वो क्या करने आए थे। वो भी तो फोटो खिंचाने आए थे। हम तो काम करके फोटो खिंचा रहे हैं।वो तो बिना काम किए फोटो खिंचा रहे हैं। इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अंदर आईए सामने भोले बाबा का मंदिर है।जैसे हमारे भोले बाबा हैं वैसे हमारे प्रदेश में भूपेश बघेल के रूप में भोले बाबा हैं और वो सबका उद्धार करते हैं।जो उनके पास जाता है उन सबकी मांग वो पूरी करते हैं। अब क्या बचा है। सब वर्ग को तो उन्होंने दिया है। अब वो मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं है।

वहीं बीजेपी ने इस बयान की निंदा की है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी अरुण वोरा के इस बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा अब चुनाव नजदीक है।टिकट पाने की लालसा में किसी को भी भगवान बना देंगे।

वहीं दुर्ग जिला के बीजेपी उपाध्यक्ष केएस चौहान के मुताबिक अरुण वोरा ने सिर्फ टिकट फिक्स करने के लिए ऐसा कहा है। बहुत शर्मनाक बयान विधायक अरुण वोरा जी का आया है।मुख्यमंत्री की तुलना भगवान शंकर जी के साथ कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री की तुलना शंकर जी के साथ कर रहे हैं उनके पिता खुद बोलते हैं कि राम नहीं रावण को पूजा कीजिए, जिनके पिता यह बोलते हैं कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उनकी तुलना आप शंकर भगवान के साथ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने तो विष पीकर संसार को बचाया था, आप घर-घर शराब बांटकर अपना पेट भर रहे हैं।अरुण वोरा ने ये बयान सिर्फ अपनी टिकट फिक्स करने के लिए दिया है।

आप और जोगी कांग्रेस ने भी बोला तीखा हमला-बीजेपी के साथ-साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आम आदमी पार्टी ने भी अरुण वोरा के बयान की आलोचना की है।युवा जोगी कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय के मुताबिक दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तुलना देवों के देव महादेव से किया है। जबकि मुख्यमंत्री के पिताजी हमेशा देवी देवताओं का अपमान करते आए हैं।

रायपुर नगर निगम सामान्य सभा स्थगित, अब 17 को होगी

रायपुर। कई महीनों बाद शुक्रवार को रायपुर नगर निगम में सामान्य सभा के लिए बैठक शुरु हुई। लेकिन सामान्य सभा शुरु होने से पहले ही हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा पार्षद दल आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान भारी हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षद दल ने समान्य सभा स्थगित करने के लिए आवेदन दिया जिस पर वोटिंग के बाद सभापति ने 17 अगस्त तक के लिए सामान्य सभा को स्थगित कर दिया।

रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा की शुरुआत हंगामेदार रही। सामान्य सभा से पहले प्रश्नकाल के दौरान भाजपा पार्षदों ने आसंदी के पास विरोध प्रदर्शन करना शुरु कर दिया। शहर में समस्याओं, जर्जर सड़क, पानी, पेयजल, बारिश, गड्ढे, जलभराव के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सत्तापक्ष पर सवालों की बौछार कर दी। जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 31 के तरह समान्य सभा स्थगित करने के लिए आवेदन किया। जिसके बाद सभापति ने वोटों के आधार पर सामान्य सभा स्थगित किया। यह पहले ही माना जा रहा था कि कई महीने बाद सामान्य सभा बुलाने के चलते यह बैठक हंगामेदार रहेगा।

रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा को लेकर सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए महापौर और सत्ताधारी पार्षदों ने अपनी रणनीति बनाया था। इस सामान्य सभा में 31 एजेंडों पर चर्चा होनी थी। जिसके तहत 31 एजेंडे में से 10 नामकरण से संबंधित हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बस, टैक्स, देरी से टैक्स देने पर चक्रवृद्धि ब्याज, निगम द्वारा जारी बॉन्ड समेत शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार खरीदें किसानों से धानः बृजमोहन

- **केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 80 फीसदी पैसा देती है**
- **1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदेगा इस वर्ष केंद्र सरकार**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों की पूरी उपज की खरीदी की व्यवस्था कर दी है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुँचाएगी और प्रयास करेगी कि प्रदेश का हर किसान प्रधानमंत्री श्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार यह झूठ बोलते हैं कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा सका। अग्रवाल ने पूछा कि प्रदेश सरकार यह बताए कि उसने प्रदेश के किसानों को कितना पैसा स्वयं की मद से दिया है? यदि केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदती है तो क्या प्रदेश सरकार किसानों की उपज का पूरा धान खरीद सके? हकीकत तो यह है कि प्रदेश की कुल उपज का 82 फीसदी धान चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं यह बात रायपुर की जनसभा में कही थी।

अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य के मुद्दे पर झूठ बोल कर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने प्रति क्विंटल धान की कीमत 2500 रुपये देने का वादा तब किया था जब समर्थन मूल्य 1750 रुपए प्रति क्विंटल था। तब कांग्रेस की सरकार को किसानों को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर 750 रुपये का बोनस देना था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने चालबाजी करते हुए उन्हें अंतर की यह राशि नहीं दी। अब धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2184 रुपये है। इसमें 750 रुपए जोड़कर इस सरकार को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर किसानों को लगभग 3000 रुपये देना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि इस दौरान हर साल केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी गई राहत का लाभ नहीं दिया। यह किसानों के साथ सरासर धोखेबाजी है। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के हक का पैसा हड़पा है। केंद्र सरकार किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदने पर सहमत हो गई है और इसमें प्रदेश की भूपेश सरकार का कोई रोल ही नहीं।

भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40.78 लाख किसान हैं जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पहुँचनी चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि पहुँच रही है। प्रदेश के 18 लाख से भी ज्यादा किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि नहीं पहुँचने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार दोषी है।

प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने आँकड़ेवार विवरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 873 रुपए बढ़ा है। खाद में सब्सिडी 35 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1.08 लाख करोड़ रुपए करके किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। पहले जब यही धान 1310 रुपए में किसान 15 क्विंटल बेचते थे तो उन्हें 19,650 रुपए मिलते थे। इस प्रकार अब किसानों को 17,500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक नंदे साहू, प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल और निश्चय वाजपेयी भी मौजूद थे।

सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है...

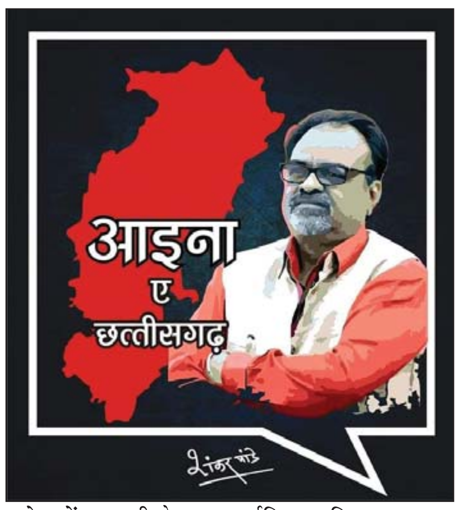

देश में आजादी के बाद सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गाँधी को करना पड़ा तो डॉ मनमोहन सिंह को इसका सामना ही नहीं करना पड़ा क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं गया ।कांग्रेस और इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी ।यह 28वीं बार है जब केंद्र की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी सरकार के लिए यह दूसरा मौका था ।पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी,जिसके खिलाफ 330 वोट पड़े थे इस बार भी नंबर के लिहाज से सरकार मजबूत स्थिति में रही।

आजादी के बाद 28 बार अविश्वास लाया गया, लेकिन एक भी बार सरकार गिरी नहीं सिवाय मोरारजी देसाई सरकार के..... उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पहली बार जवाहर लाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया भारत का इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार,पी वी नरसिम्हा राव- 3 बार,लाल बहादुर शास्त्री- 3 बार,मोरारजी देसाई 2 बार ,जवाहर नेहरू, राजीव गांधी तथा अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध 1-1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ।नरेंद्र मोदी (2018 में) 1 बार,हाल ही में दूसरी बार.... । देश का पहलाअविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ आया था ।आजादी के बाद देश में पहला अविश्वास प्रस्ताव तीसरी लोकसभा संसद में पेश किया गया ।उस समय जवाहर लाल नेहरू पीएम थे और 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद आचार्य जेबी कृपलानी उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये थे ।हालांकि, 347 सांसदों के विरोध के बाद प्रस्ताव फेल हो गया और सिर्फ 62 सांसदों ने इसका समर्थन किया था ।लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।पहली बार 1964 में एनसी चटर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाए और 307 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया ।सिर्फ 50 सांसदों का ही समर्थन मिला, जिसकी वजह से प्रस्ताव खारिज हो गया?1965 में लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ एसएन द्विवेदी अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, जिसे 44 सासंदों का समर्थन मिला ।315 ने इसके खिलाफ वोटिंग की। इसी साल उनकी सरकार के खिलाफ एक और अविश्वास लाया गया, लेकिन 318 सांसदों ने उसके खिलाफ वोटिंग करके इसे गिरा दिया। स्वतंत्र पार्टी के एमआर मसानी यह अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।

इंदिरा गांधी ने 15 बार किया था सामना.....

इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।हालांकि,एक भी बार उनकी सरकार नहीं गिरी ।1966 में दो बार,1967 में दो बार,1968 में दो बार,1969 में एक बार,1970 में एक बार,1973 में एक बार, 1974 में दो बार और 1975 में 1 बार,1981 और 1982 में भी 1-1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।1981 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडीज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये,लेकिन उन्हें 278 सांसदों का समर्थन मिला और प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 92 वोट डले थे.

जब गिर गई थी मोरारजी देसाई की सरकार......

साल 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष सीएम स्टीफन अविश्वास प्रस्ताव लाये थे,लेकिन यह भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। एक

साल बाद 1979 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।इस बार प्रस्ताव लाने वाले वाई बी चव्हाण थे,लेकिन देसाई की सरकार गिर गई....उन्होंने प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया और राजनीति से भी संन्यास ले लिया था ।राजीव गांधी और अटल के खिलाफ 1-1 बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ।साल 1992 और 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ।1987 में राजीव गांधी की सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके खिलाफ वोट करने वालों की संख्या ज्यादा थी इसलिए यह खारिज हो गया ।साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अविश्वास प्रस्ताव लाई थीं। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हाल ही में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ।

रिटायर अफसरों पर छ्ग सरकार मेहरबान....!

छत्तीसगढ़ में पूर्व अफसरों पर अधिक विश्वास जताया जा रहा है,रिटायर होने के बाद आईएएस,आईपीएस औरआईएफएस अफसरों को संविदा नियुक्ति देकर काम चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं

है कि फ्रेस अफसरों की कमी है पर पुराने अफसरों के अनुभवी होने का लाभ मिलना भी एक प्रमुख कारण हो सकता है वहीं सरकार का करीबी होना भी विशेष योग्यता का पैमाना है, केवल प्रमोटी आईएएस अनिल टुटेजा ही अपवाद हैं जिन्हें संविदा नियुक्ति नहीं मिली पर उसके पीछे ईडी आदि की जाँच बड़ा कारण रहा है ।सूबे में संविदा नियुक्ति की बाढ़ सी आ गई है ।प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि सरकार %संविदा% अफसरों के भरोसे चल रही है।%संविदा% पाने वाले अफसरों के मातहत इससे नाखुश हैं ।खुलकर कोई कुछ नहीं कहता,मगर दबी जुबां से प्रशासनिक गलियारों में इस पर जमकर चर्चा होने लगी है।आलम यह है कि संविदा अफसरों की सूची बनाकर किस्सागोई की जाने लगी है ।अब पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग पर रेग्युलर अफसरों की नजरें टेढ़ी हो रही हैं। सूबे में संविदा पाने वाले अफसरों की लंबी सूची है ।आईएएस बिरादरी में विवेक ढांड,अजय सिंह, एम के राउत,सुनील कुजूर,आर पी मंडल, डॉक्टर आलोक शुक्ला, डी डी सिंह,धनंजय देवांगन, निरंजन दास, टामन सोनवानी,दिलीप वासनिकर,अशोक अग्रवाल,अमृत खलको आदि के नाम शामिल हैं तो वहीं आईपीएस बिरादरी से डीएम अवस्थी को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग मिली और अब संजय पिल्ले को सरकार पोस्टिंग देने जा रही है गृह विभाग ने जीएडी को फाइल भेज दी है ।पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग पाने वालों में आईएफएस अफसर भी पीछे नहीं है ।पीसीसीएफ रहे राकेश चतुर्वेदी और संजय शुक्ला दोनों अफसरों को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग मिली। आईएफएस एस एस बजाज भी रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग पाने वाले अफसर रहे। ये शाश्वत सत्य है कि जब तक ओहदा, तब तक मान-सम्मान....वर्ना कई नामी ब्यूरोक्रेट हुए हैं, जिनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं हुआ। यदा उनके किए कामों पर चर्चा ज़रूर हो जाती है। वैसे अभी छ्ग लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोक आयोग में भी कुछ रिटायर अफसरों को समायोजित किया जाना तय माना जा रहा है।

महादेव की कृपा अब तो नहीं रही.......!

छ्ग पुलिस प्रशासनिक सेवा के 2अफसरों पर महादेव की कृपा बनी हुई थी। भिलाई दुर्ग के महादेव की कृपा के चलते इन पर कुछ बड़े अफसरों की भी कृपा बनी हुई थी यह बात और है कि अब कृपा करनेवाले महादेव के बड़े भक्त ज़ब से दुबई चले गये हैं, ईडी की जाँच शुरू हो गई है,एक वरिष्ठ अफसर की वापसी हो गई है तब से चर्चा तेज है कि दोनों अफसरों के जिले में अदला बदली हो सकती है...? सावन माह में महादेव की नाराजगी का क्या परिणाम निकलता है इसका इंतजार इनके साथी तथा मातहत अफसर भी कर रहे हैं....?

और अब बस....

- किस संभाग में कमिश्नर और एक कलेक्टर एक ही बैच के आईएएस हैं... !दोनों में ठन भी गई है.... !
- एक अफसर अपनी करीब डेढ़ दर्जन मौसी और एक मामा से रिश्ता निभाते-निभाते परेशान से हो गये हैं
- एसपी की तबादला सूची आखिर किसके कारण रुकी हुई है.... !
- ईमानदारी आखिर किस आईजी को भारी पड़ गई....?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भरोसे का सम्मेलन सफलता की झांकी है : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की सफलता की झांकी है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गरिमामय उपस्थिति में कांग्रेस सरकार अपनी उसी उपलब्धियों का प्रदर्शन हितग्राहियों के साथ

करेगी। साढ़े चार साल पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से वायदा किया था उसको तो पूरा किया ही उसके अलावा राज्य की जनता के भलाई के लिये कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाये जिससे राज्य के हर वर्ग के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन आया। भरोसे का सम्मेलन उसी की जीवंत झांकी है जिसमें हितग्राही कांग्रेस पर कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताते है। कांग्रेस राज के साढ़े चार साल में लोगो को भरोसा कांग्रेस के प्रति और बढ़ा है। यही कारण है कि 2018 का विधानसभा चुनाव दो तिहाई से जीतने के बाद कांग्रेस ने लगातार पांच उपचुनाव नगरी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत से जनता का भरोसा जीता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के न्याय की बयार बह रही है। कांग्रेस सरकार युवाओं, किसानों मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति सभी के साथ न्याय कर रही राज्य की न्याय योजनाये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंजीकृत भूमिहीन परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है।

आम नागरिक अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रहा : चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले अब इतने बढ़ चुके हैं कि वे सरेआम चाकूबाजी करके आतंक फैलाने में लगे हैं। प्रदेश में

जंगलराज कायम हो चला है। राजधानी में चाकू गोदकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल करने और दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र के चोहरा गाँव में चाकू गोदकर एक युवक की हत्या कर दिए जाने की ताजा वारदातों का हवाला देते हुए श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश में अमन पसंद आम नागरिक अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ तेजी से अपराध की ओर करवट ले रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि मणिपुर की हिंसा पर सियासत कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों को हिंसा और अपराधों का गढ़ बनते जा रहे छत्तीसगढ़ की कतई चिंता नहीं है। प्रदेश की भूपेश सरकार की नाक के नीचे राजधानी में चाकूबाज लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री बघेल के गृह जिले में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और मुख्यमंत्री इसके बजाय मणिपुर हिंसा को लेकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। श्री चंदेल ने नसीहत दी है कि मुख्यमंत्री इधर-उधर की बातों में समय जाया करने के बजाय प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के अपने उस दायित्व पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है।

धान खरीदी राज्य सरकार अपने दम पर करती है: शुक्ला

रायपुर। धान खरीदी पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। धान खरीदी का पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार

के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार मार्कफेंड के माध्यम से विभिन्न बैंको से कर्ज लेकर धान खरीदी करती है। किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रूपये, देश ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत भूपेश सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रम फैलाने के लिये जबरिया वाहवाही लेने के लिये राजनीति कर रहे है। पिछले वर्ष 107 लाख मीट्रिक धान की खरीदी कांग्रेस सरकार ने किया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में रमन सरकार के द्वारा इसका आधा धान ही खरीदा जाता था। इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र का राज्यों से चावल और अन्य अनाज खरीदना और राज्य का अपने किसानों से धान खरीदना दोनों अलग-अलग योजना है। राज्य अपने किसानों को उसकी उपज की पूरी कीमत देने अपने संसाधनों से धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ के किसानों से भूपेश सरकार ने 2660 रू. में धान खरीदा है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में तो किसानों को 1000-1200 में धान बेचना पड़ता है।

विजय बघेल ने झूठ बोलकर राज्य की छवि खराब किया: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सांसद विजय बघेल ने लोकसभा में झूठ बोलकर तथा गलत वक्तव्य देकर प्रदेश की छवि बिगाड़ने की कोशिश किया है। विजय बघेल मोदी की चाटुकारिता में राज्य के खिलाफ बयान दिया जो अपराध की घटनायें

छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही उसके बारे में गलत बयानी किया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 62 प्रतिशत की कमी आई है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधो के मामले में छत्तीसगढ़ 18वें क्रम पर है, राज्य में महिलायें रमन राज से ज्यादा सुरक्षित हुयी है, राज्य में गोधन न्याय योजना से महिलाओं को, किसानों को, गोपालकों को लाभ हो रहा है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब कीमत मिल रहा है लेकिन विजय बघेल ने इन सारे मसलो पर सदन में झूठ बोला। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार और भाजपा के शीर्ष नेता भूपेश पर भरोसे की छत्तीसगढ़ सरकार से भयभीत है। आगामी विधानसभा चुनाव में आसन्न हार का डर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों में भी इस कदर हावी है की सदन में झूठ बोलने से भी नहीं चूक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने लोकतंत्र के मंदिर, लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों बहस के दौरान जवाबदेही के बजाय छत्तीसगढ़ को लेकर झूठे आरोप लगाए गए। बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अडानी कोल खदान आवंटित करने का आरोप लगाया।

कायाकल्प ही नहीं तो किस बात का संकल्प : कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस द्वारा किये जा रहे संकल्प शिविर अभियान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले पौने पांच सालों तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसे लेकर वे जनता के बीच जा सके। उन्होंने कहा कि

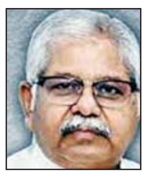

भेंट-मुलाकात का हलिया अभियान तो मूलत: डाँट-फटकार का कार्यक्रम ही सिद्ध हुआ है जो पुरी तरह से सुनियोजित कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रखा है आज कांग्रेस सरकार के कुनीतियों से प्रदेश की जनता अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिये भी तरह रहे हैं, अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, भ्रष्टाचार को चरम पर रख कर हर चीज को अपने अवैध कमाई का जरिया बनाकर रखा गया है युवाओं को पौने पांच सालों तक छला गया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सरकार के वादाखिलाफ़ी करने के कारण अधिकारी कर्मचारियों को पुरा पांच साल हड़ताल में ही गुजारना पड़ा, भ्रष्टाचारी में लिप्त कांग्रेस की इस सरकार ने प्रदेश की लाखों परिवार के सर से छत छिन लिया, जल जीवन मिशन का बुरा हाल कर दिया। छत्तीसगढ़ की ढ़ाई करोड़ जनता की आशा का केन्द्र जहां विकास की रूपरेखा तय होती है वहां की जनता भूपेश सरकार के शासन में सभी मूलभूत सुविधाओं के लिये तरस रही है।

3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार खरीदे किसानों से धान

केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए 80 फीसदी पैसा देती है : बृजमोहन

- 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदेगा इस वर्ष केंद्र सरकार
- प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 873 रुपए बढ़ा, खाद में सब्सिडी बढ़ाकर 1.08 लाख करोड़ करके किसानों को दी बड़ी राहत दी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों की पूरी उपज की खरीदी की व्यवस्था कर दी है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुँचाएगी और प्रयास करेगी कि प्रदेश का हर किसान प्रधानमंत्री श्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे ।एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार यह झूठ बोलते हैं कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा सका। अग्रवाल ने पूछा कि प्रदेश सरकार यह बताए कि उसने प्रदेश के किसानों को कितना पैसा स्वयं की मद से दिया है? यदि केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदती है तो क्या प्रदेश सरकार किसानों की उपज का पूरा धान खरीद सके? हकीकत तो यह है कि प्रदेश की कुल उपज का 82 फीसदी धान चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं यह बात रायपुर की जनसभा में कही थी।

ब्लैक आऊट होने पर तुरंत बिजली संयंत्र शुरु करने हुआ मॉकड्रिल

रायपुर । प्रदेश में आकस्मिक ब्लैक आउट होने की स्थिति में ताप विद्युत गृहों को पुर्नसंचालित करने हेतु हसदेव बांगो जल विद्युत गृह से स्टार्ट अप पॉवर सप्लाई करने संबंधी एक मॉकड्रिल (पूर्वाभ्यास) छत्तीसगढ़ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में सफलतापूर्वक किया गया। पॉवर कंपनी के फील्ड में तैनात कर्मचारियों एवं अभियंताओं द्वारा तत्परतापूर्वक दूसरी लाईन को आईलैण्डेड स्कीम में शामिल करते हुए कोरबा - पश्चिम के संयंत्रों को शुरू करने हेतु 1 घंटा 24 मिनट में बांगो जल विद्युत संयंत्र से बिजली पहुंचायी गयी ।गौरतलब है कि अचानक ब्लैक आऊट होने की स्थिति में पावर प्लांटों को फिर से स्टार्ट करना कठिन होता है, इसके लिए तुरंत बिजली की आवश्यकता पड़ती है।

ग्राम टेकारी में शिक्षकों की कमी, डहरिया को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। जिले के ग्राम टेकारी के ग्रामीणों को उच्चतर माध्यमिक शाला खुलवाना महंगा पड़ रहा है। जनभागीदारी स्कूल खोलने से लेकर उसके हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के बाद से पिछले शैक्षणिक सत्र तक वे ग्रामीण व्यवस्था के तहत जुगाड़ कर तीनों? स्कूलों के लिये गुरुजनों की व्यवस्था में वे करीबन 25 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं और अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। वे नौनिहालों की बेहतर भविष्य के खातिर उग्र कदम उठाने की तैय्यारी में है पर इसके पूर्व गुरूजनो सहित कार्यालयीन स्टाफ की कमी को दूर करने की मांग को ले अभी अभी शिक्षा विभाग के प्रभार सम्हालने वाले शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे सहित क्षेत्रीय विधायक व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को ज्ञापन सौंपा

गया है।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम टेकारी में स्वतंत्रता के बाद सन् 1948 से शासकीय प्राथमिक शाला है । सन् 1954 में यहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खुला । ग्रामीणों की मांग पर सन् 2001 में जनभागीदारी उच्च माध्यमिक शाला खोला गया जिसका शासकीयकरण पश्चात सन् 2011मे उच्चतर माध्यमिक शाला के रूप में उन्नयन किया गया। उन्नयन के समय से ही इस विद्यालय में भौतिकी व हिंदी के व्याख्याता का पद रिक्त है व बीते दो वर्षों से प्राचार्य व रसायन विज्ञान के व्याख्याता का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। भौतिकी विषय के रिक्त पद के विरुद्ध रायपुर के डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला डब्लू आर एस कालोनी में पदस्थ अतिशेष व्याख्याता का वेतन टेकारी के इस स्कूल से आहरित किया जा रहा है जबकि यह व्याख्याता शहर के स्कूल को छोड़ टेकारी के स्कूल में सेवा देने तैयार है व विधिवत विभागीय आवेदन भी दे चुका है। इसके अतिरिक्त इस स्कूल में सहायक शिक्षक विज्ञान , ग्रंथपाल व सहायक ग्रेड - 3 के एक एक पद व नियमित मृत्यु के 3 पद रिक्त है। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शाला में बीते 1 मई से प्रधानपाठक व अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पद अरसे से रिक्त पड़ा हुआ है। प्राथमिक शाला में बीते 1 जून से प्रधान पाठक का पद रिक्त है। इस शैक्षणिक सत्र में इस विद्यालय में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 102 है लेकिन शिक्षक दो हैं जिसमें से एक संकुल समन्वयक बना दिये जाने के कारण विद्यार्थियों को अध्यापन करा पाने में असमर्थ है। शिक्षकों की कमी के बाद भी यहां पदस्थ एक और शिक्षक को व्यवस्था के तहत विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आरंग से बाहर पदस्थ कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार जनभागीदारी स्कूल खुलने के समय से लेकर अब तक गुरुजनों की व्यवस्था में ग्रामीण जुगाड़ कर तकरीबन 25 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं जिसमें उन्नयन बाद करीबन 13 लाख रुपए खर्च किया गया है ।

48 दिनों में 49 शराब कोचिये थाना अमला के हत्थे चढ़े , इनमें से 7 जेल दाखिल किये गये

रायपुर । मंदिर हसौद थाना अमला ने बीते 48 दिनों के भीतर अवैध शराब के 49 मामले पकड़ने में सफलता हासिल की है जिसमें से 7 मामलों में कोचियो के पास से 5 लीटर से अधिक शराब जप्त होने की वजह से इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के गैरजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर इन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । शेष मामलों में से 2 में 5 लीटर से कम शराब जप्त होने के कारण आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के जमानतीय अपराध में आरोपी के गिरफ्तारी पश्चात जमानत पर छोड़ दिया गया। बाकी मामले शराब पिलाने के जमानतीय अपराध के हैं।

ज्ञातव्य हो कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नशा के खिलाफ हैलो जिंदगी अभियान की शुरुआत थाना अमला द्वारा की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा पूर्व थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा के स्थानान्तरण पश्चात इस थाना में नवनियुक्त थाना प्रभारी रोहित मालेकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाये जा रहे इस अभियान के तहत 5 लीटर से अधिक शराब सहित ग्राम पलौद के नेकी कुर्रे 30 पौव्वा , कुरूद के धर्मेंद्र धृतलहरे 40 पौव्वा , मंदिर हसौद के खोरबाहरा गेड़े 33 पौव्वा , चंदखुरी फार्म के मोहित उर्फ मोंटू 48 पौव्वा , राखी के रघुवीर जांगड़े 40 पौव्वा , धमनी के छन्नू निर्मलकर 30 पौव्वा व बड़गांव के प्रेमू यादव 30 पौव्वा शराब सहित थाना अमला के हत्थे चढ़े हैं ।

साढ़े 4 साल में 39 हजार से ज्यादा बच्चों की मृत्यु, भाजपा ने बाल आयोग से की शिकायत, कहा- जांच हो

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। बीजेपी ने साढ़े चार सालों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में 0 से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में शिकायत कर जांच की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में 5 साल तक के 39 हजार से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नेतृत्व में सांसद विजय बघेल, गोमती साय, गुहाराम अजगले ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मामले की शिकायत कर जांच की मांग की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को सौंप गए लेटर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदवे की ओर से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 से जून 2023 तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु आंकड़ा 29267 है, जो काफी चिंताजनक है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.